

कीमतें और मुद्रास्फीति

निम्न खाद्य मुद्रास्फीति की मदद से, 2014 से मुद्रास्फीति सामान्य दर्ज की गयी है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, खाद्य और पेय-पदार्थ संबंधी मुद्रास्फीति में अलग प्रकार से रुझान पर रहा है। मुख्यतः सब्जियों, फलों और दालों की कीमत में वृद्धि की मदद से, खाद्य मुद्रास्फीति में ऊर्ध्वमुखी रुझान रहा है। हालांकि, कुछ अपवाद के साथ दाल जैसी अधिकांश कृषि संबंधी अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता का अधोमुखी रुझान रहा। जुलाई 2018 से शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति, ग्रामीण-सीपीआई मुद्रास्फीति से लगातार ऊंची रही है। यह पहले के रुझानों के विपरीत है जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से ऊंची रहती थी। अधिकांश राज्यों की मुद्रास्फीति में गिरावट रही है यद्यपि समय के साथ-साथ मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है। 2012 से स्फीति की गति में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान अवधि में, मुद्रास्फीति का प्रेषण गैर-कोर घटकों से कोर घटकों की तरफ न्यून रहा है।

परिचय

5.1 विगत पाँच दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के साक्ष्य रहे हैं। (विश्व बैंक-2019) विश्व के लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति में कमी आई है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भी उसी अवधि में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया गया है। 1993 में मुद्रास्फीति 118.7 प्रतिशत के साथ शिखर पर थी और तत्पश्चात उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में 2018 में 4.8 प्रतिशत की कमी आई (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2019)। मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कई सहायक कारण हो सकते हैं जैसे समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति की स्वीकार्यता, ऋण और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा की मजबूती दे और लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति तंत्र का विकास। चौबीस उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लक्ष्यात्मक स्फीति तंत्र की मौद्रिक नीति का सूत्रपात किया है (विश्व बैंक-2019)। भारत ने 5 अगस्त, 2016 को लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति का

सूत्रपात किया जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होनेवाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगी।

5.2 भारत में, मुद्रास्फीति 2014 से अनतिक्रम का साक्ष्य रही है। हालांकि हाल में ही इसमें चढ़ाव दिखा है। हेडलाइन उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सी.पी.आई. सी.) मुद्रास्फीति-2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019 तक) में 4.1 प्रतिशत थी जो कि 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक) में 3.7 प्रतिशत थी। थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) मुद्रास्फीति भी कम रही है। यद्यपि डब्ल्यू. पी. आई. मुद्रास्फीति में 2015-16 और 2018-19 के बीच वृद्धि देखी गई है, तथापि इसमें 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक) में 4.7 प्रतिशत से 2019-20 (अप्रैल से नवम्बर, 2019 तक) के दौरान 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी (तालिका 1)। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट, 2014-15 और 2018-19 के बीच मुद्रास्फीति में देखी गई प्रबल कमी में एक प्रमुख सहायक घटक रही है। साथ ही साथ, यह भी देखा गया है कि मुद्रास्फीति संबंधी गतिकी में विस्थापन रहा है। 2013-14 से मुद्रास्फीति

तालिका-1. विभिन्न कीमत सूचियों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19*	2019-20*
डब्ल्यू. पी. आई.	5.2	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3	4.7	1.5 (P)
सी.पी.आई.-सी.	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	3.7	4.1 (P)
सी.पी.आई.-आई.	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	4.9	7.6
डब्ल्यू.								
सी.पी.आई.-ए.एल.	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	1.7	7.3
सी.पी.आई.-आर.एल.	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	1.9	7.1

स्रोत: आर्थिक, सलाहकार कार्यालय, थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई. टी.), सी.पी.आई.-सी. के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) और सी.पी.आई. (आई. डब्ल्यू.), सी.पी.आई.-ए.एल. और सी.पी.आई.-आर.एल. के लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: 2013-14 के लिए सी.पी.आई.-सी. मुद्रास्फीति पुरानी श्रृंखला 2010=100 पर आधारित है; (पी.-अनन्तम; सी. का अर्थ संयुक्त, आई. डब्ल्यू. का अर्थ औद्योगिक कामगार, ए.एल. का अर्थ कृषि संबंधी श्रमिक और आर.एल. का अर्थ ग्रामीण श्रमिक होता है।

*2019-20 सी.पी.आई.-सी, डब्ल्यू पी आई, सी.पी.आई.-ए.एल, सी.पी.आई.-आर.एल. के लिए अप्रैल से दिसम्बर 2019 से संबंधित है और सी.पी.आई.-डब्ल्यू हेतु अप्रैल से नवम्बर 2019 से संबंधित है।

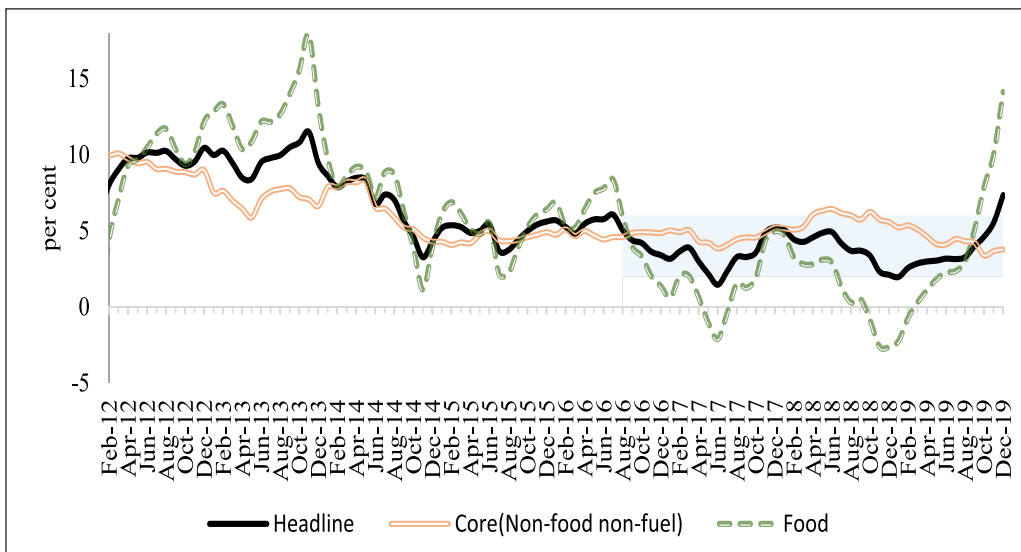
के औसतन स्तरों में अत्यधिक गिरावट हुई है। न केवल मुद्रास्फीति के औसतन स्तरों में गिरावट आई है, बल्कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के अधिकतम स्तर अब भी बहुत कम हैं। इसका अलावा, हमने यह देखा है कि सी.पी.आई.-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) के अनुसार 2012 के बाद से कोर मुद्रास्फीति की ओर हेडलाइन मुद्रास्फीति का अभिसरण हुआ है।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां

5.3 सी.पी.आई.-सी. पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2014 से अधोमुखी गिरावट हो रही है (चित्र-1)

औसत सी.पी.आई.-सी. हेडलाइन मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत थी, उसमें 2018-19 में लगभग 3.4 प्रतिशत तक की अनवरत गिरावट हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट इसका मुख्य कारण रहा है, जिसमें 2014-15 में 6.4 प्रतिशत से 2018-19 में 0.1 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है। 2019-20 में, अगस्त, 2019 से हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति के अंकों में थोड़ा इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर, दिसंबर, 2019 में सी.पी.आई.सी. हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत तक कायम थी, जबकि सी.पी.आई.-खाद्य मुद्रास्फीति

चित्र 1: सी.पी.आई.-सी. हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति



स्रोत: एन.एस.ओ.

तालिका 2: उपरोक्त कीमत सूचकांक संयुक्त के चुनिंदा समूहों में मुद्रास्फीति आधार 2012 (प्रतिशत में)

विवरण	Weights	2017-18	2018-19	2019-20#	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19 (P)
सभी समूह	100	3.6	3.4	4.1	3.2	3.3	4.0	4.6	5.5	7.4
सी.एफ.पी.आई.	39.1	1.8	0.1	5.3	2.4	3.0	5.1	7.9	10.0	14.1
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	2.2	0.7	4.8	2.3	3.0	4.7	6.9	8.7	12.2
अनाज और उत्पाद	9.7	3.5	2.1	2.0	1.3	1.3	1.7	2.2	3.7	4.4
मीट और मछली	3.6	3.2	4.0	9.0	9.1	8.5	10.3	9.8	9.4	9.6
अंडा	0.4	3.6	2.3	3.4	0.6	0.3	3.3	6.3	6.2	8.8
दुध और दुग्धोत्पाद	6.6	4.1	1.8	1.8	1.1	1.5	1.8	3.1	3.5	4.2
तेल और वसा	3.6	1.6	2.1	1.4	0.9	0.6	1.2	2.0	2.6	3.1
फल	2.9	4.6	2.3	-0.5	-0.9	-0.8	0.8	4.1	3.2	4.4
सब्जियां	6.0	5.8	-5.2	17.6	2.8	6.9	15.5	26.1	36.1	60.5
दालें और उत्पाद	2.4	-21.0	-8.3	7.8	6.8	6.9	8.4	11.7	13.9	15.4
चीनी और मिठाइयां	1.4	6.1	-7.0	-0.2	-2.1	-2.4	-0.4	1.3	2.1	3.4
इंधन और प्रकाश	6.8	6.2	5.7	-0.1	-0.3	-1.7	-2.2	-2.0	-1.9	0.7
सीपीआई खाद्य और इंधन समूह को छोड़कर	47.3	4.6	5.8	4.1	4.5	4.3	4.2	3.4	3.6	3.8

स्रोत: एन.एस.ओ.

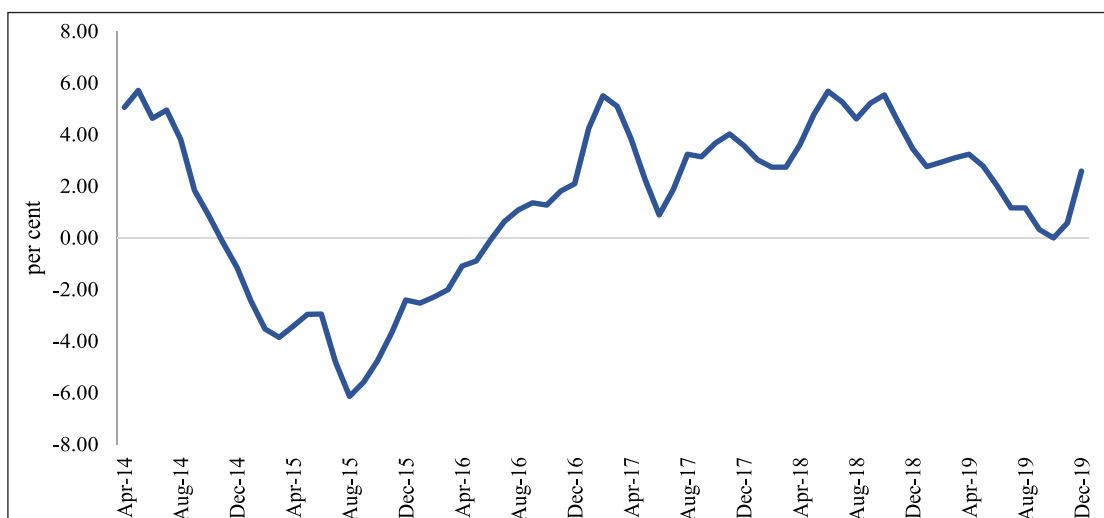
टिप्पणी: पी.: अनंतिम, *उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक, रु अप्रैल से दिसंबर 2019 तक

में 14.1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यतः सब्जी की कीमतों में वृद्धि द्वारा संचालित थी। दिसंबर, 2019 में कोर (अखाद्य और गैर ईंधन) मुद्रास्फीति में 3.8 प्रतिशत तक की थोड़ी गिरावट हुई है।

5.4 2019-20 के दौरान, डब्ल्यू.पी.आई. पर आधारित

मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से नवंबर 2019 में 0.6 प्रतिशत तक की लगातार गिरावट होती जा रही है (चित्र-2)। 2017-18 और 2018-19 के बीच वार्षिक आधार पर जिस खाद्य सूचकांक में गिरावट हुई है, उसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2019) के दौरान इज़ाफा देखा गया है। (तालिका-3)

चित्र 2: डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति



स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डी.पी.आई.आई.टी.

तालिका 3: थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति- आधार वर्ष 2011-12 (प्रतिशत)

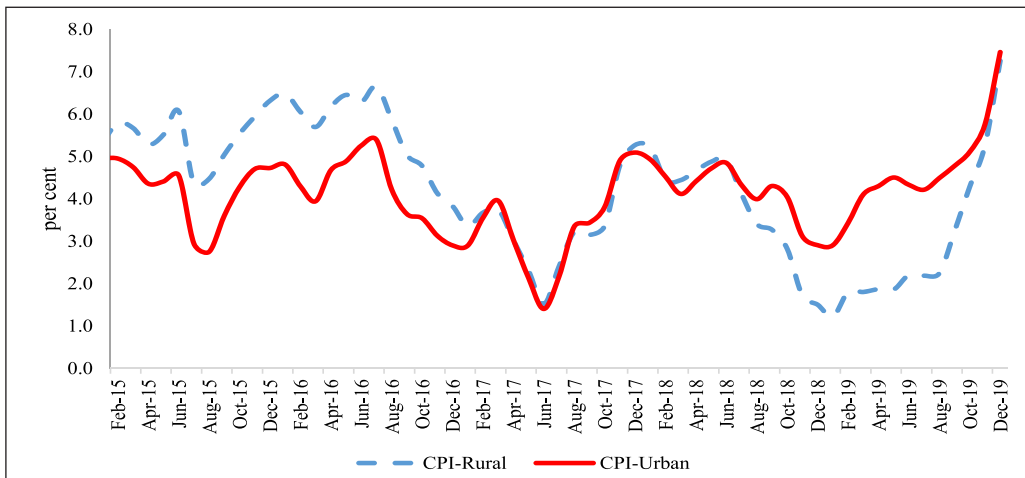
	Weight	2017-18	2018-19	2019-20*	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19(P)	Dec-19(P)
सभी उत्पाद	100	3.0	4.3	1.5	1.2	1.2	0.3	0.0	0.6	2.6
खाद्य सूचकांक	24.4	1.9	0.6	6.7	4.9	5.9	6.1	7.6	9.0	11.0
खाद्य सामग्री	15.3	2.1	0.4	8.6	6.6	7.8	7.5	9.8	11.1	13.2
अनाज	2.8	0.3	5.5	8.2	8.7	8.5	8.7	8.3	7.9	7.7
दालों	0.6	-27.1	-9.4	17.3	20.0	16.4	17.9	16.6	16.6	13.1
सब्जियों	1.9	18.8	-8.4	31.4	10.5	12.9	19.3	39.0	45.3	69.7
फलों	1.6	5.0	-1.7	4.4	15.4	19.8	6.7	2.7	4.3	3.5
दूध	4.4	4.0	2.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	2.6
अंडा, मीट और मछली	2.4	2.0	1.7	6.6	3.6	7.0	7.7	7.6	8.2	6.2
खाद्योत्पाद	9.1	1.6	0.9	3.2	1.8	2.2	3.6	3.8	5.0	6.9
वनस्पति और पशु तेल वसा	2.6	2.2	7.5	-2.4	-6.6	-4.1	-2.8	-1.9	2.2	9.7
चीनी	1.1	3.4	-10.7	4.0	-1.0	1.4	4.7	3.2	3.1	4.7
इंधन और बिजली	13.2	8.1	11.6	-3.1	-3.6	-3.5	-6.7	-8.1	-7.3	-1.5
गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद (मुख्य)	55.1	3.0	4.2	-0.3	0.0	-0.4	-1.2	-1.8	-1.9	-1.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डी.पी.आई.आई.टी.पी.: अनंतिम

5.5 जुलाई 2018 से, सी.पी.आई.-शहरी-मुद्रास्फीति-सी.पी.आई.-ग्रामीण मुद्रास्फीति से लगातार ऊपर रही है (चित्र-3)। यह प्रारम्भिक अनुभव के विपरीत है, जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति मुख्यतः शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रहा है। यह विचलन मुख्यतः इस अवधि के दौरान देखे गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खाद्य मुद्रास्फीति की विभेदक दरों के

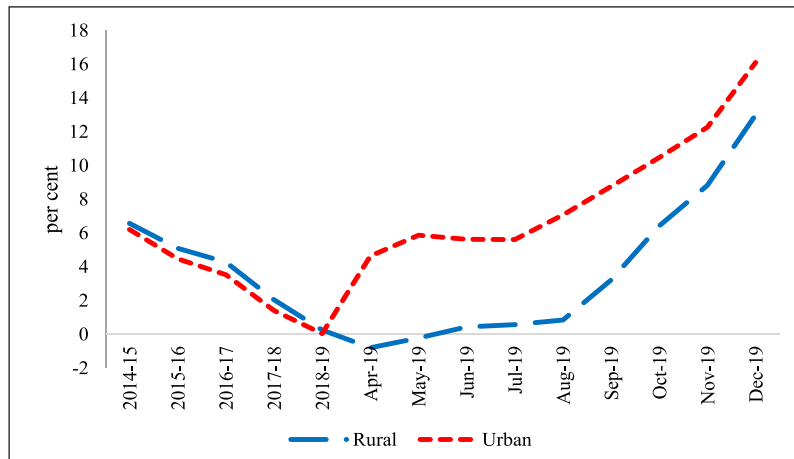
कारण हुआ है। 2019-20 की अवधि में रुझानों में अकस्मात परिवर्तन हुआ। जुलाई, 2019 से शहरी क्षेत्रों की खाद्य मुद्रास्फीति काफी ऊंची दर्ज की गई (चित्र 4)। इस अवधि के दौरान ग्रामीण-शहरी खाद्य मुद्रास्फीति में विचलन मुख्यतः अनाज, दालें, सब्जियां, अंडे आदि के कारण हुआ था (चित्र 5 (क) से (घ) तक)।

चित्र 3: सी.पी.आई. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति



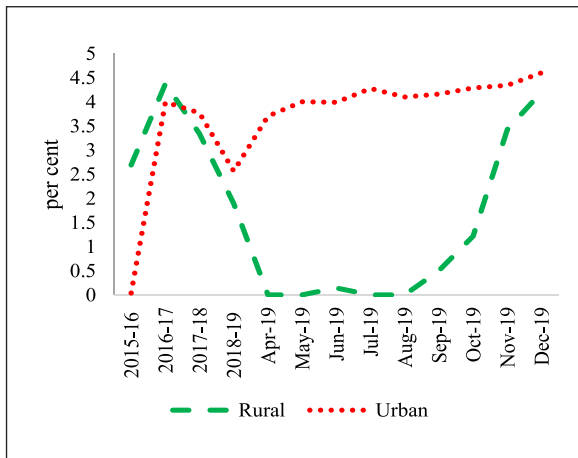
स्रोत: एन.एस.ओ.

चित्र 4: ग्रामीण शहरी खाद्य मुद्रास्फीति

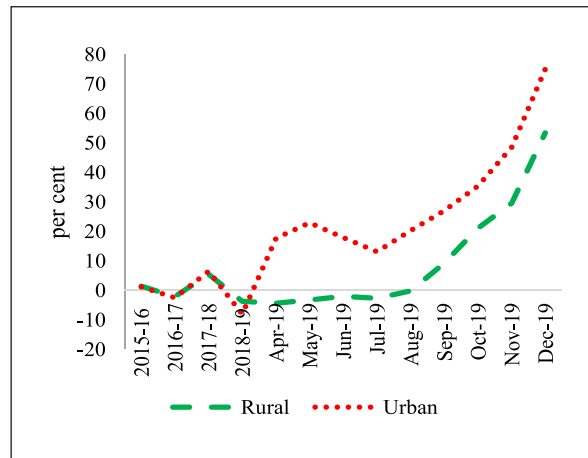


स्रोत: एन.एस.ओ.,

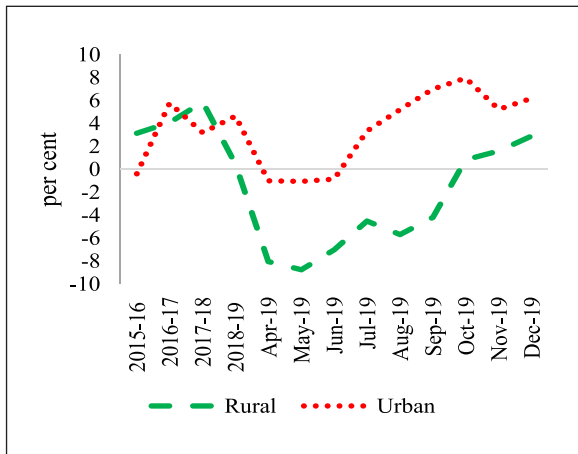
चित्र 5 (क): अनाज की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर



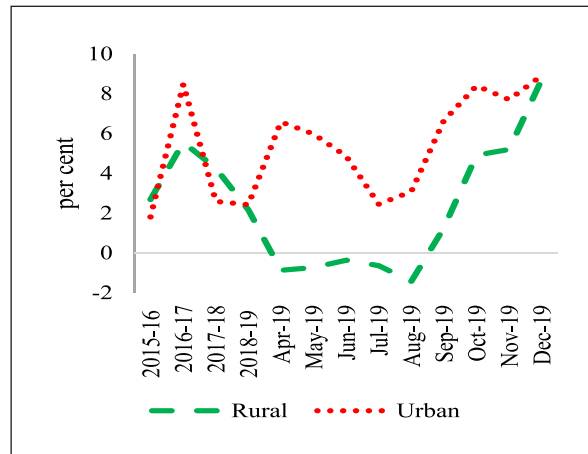
चित्र 5 (ख): सब्जियों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर



चित्र 5 (ग): फलों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर

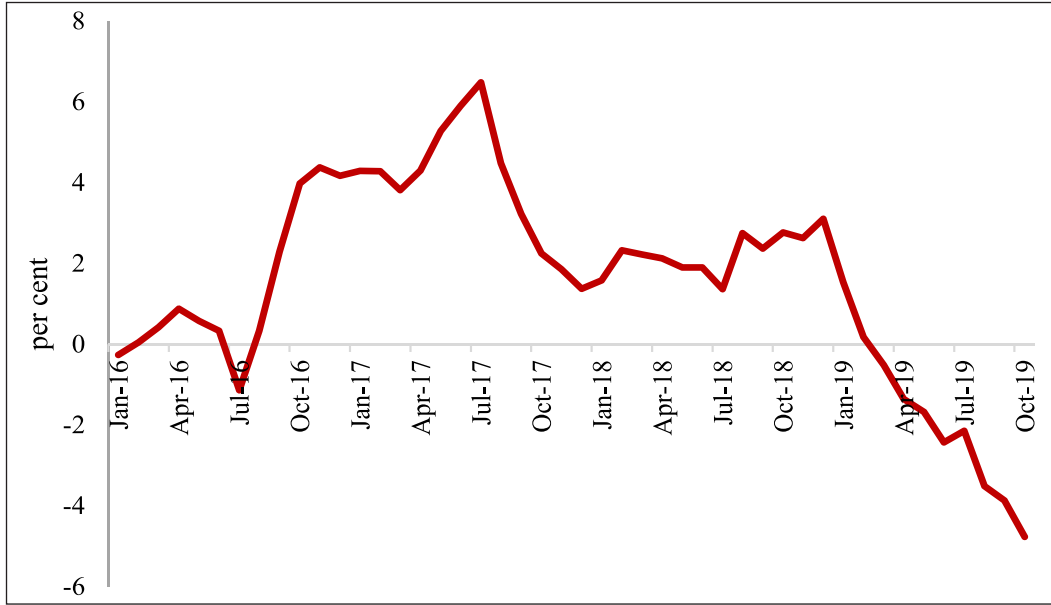


चित्र 5 (घ): अण्डों की सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर



स्रोत: एन.एस.ओ.

चित्र 6: 2016 से 2019 के दौरान कृषि-संबंधी कामगारों के लिए औसत वास्तविक मजदूरी दर की साल दर साल वृद्धि (अक्टूबर, 2019 तक)



स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

टिप्पणी: वास्तविक मजदूरी दर की गणना सामान्य कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर को सीपीआई.एएल से विभाजित करके की गयी है।

5.6 ग्रामीण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट फिसलन का कारण वास्तविक ग्रामीण मेहनताना की वृद्धि में मंदी है। (चित्र 6)।

5.7 ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में विचलन केवल खाद्य घटकों में ही नहीं देखा जाता है अपितु यह विचलन अन्य घटकों में भी देखा जाता है। नीचे दिया गया चित्र-7 ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति घटकवार दर्शाता है। शहरी क्षेत्र में कपड़ों और जूतों में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मुद्रास्फीति 3.3 प्रतिशत थी जो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति से लगभग 3 प्रतिशत अधिक थी। पान, तंबाकू और मादक प्रदार्थों, ईंधन और बिजली तथा अन्य विविध गुणों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। इस विविध बास्केट घरेलू सामान और सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, शिक्षा, व्यक्तिगत देखभाल और सामान इत्यादि हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य और कपड़ा एवं जूता समूह से जुड़े समग्र भारता के चलते ग्रामीण क्षेत्र में देखी गई समग्र मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत थी जो वर्ष

2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में शहरी क्षेत्र में देखी गई समग्र मुद्रास्फीति के 5.0 प्रतिशत से कम थी। कपड़ों और जूतों, ईंधन और बिजली जैसी मदों में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट वास्तविक ग्रामीण मेहनताने की वृद्धि में कमी के कारण हो सकता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल आदि जैसी मदों में ग्रामीण मूल्य सूचकांक में उछाल से ग्रामीण क्षेत्रों में इन मदों की वहीनीयता का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है।

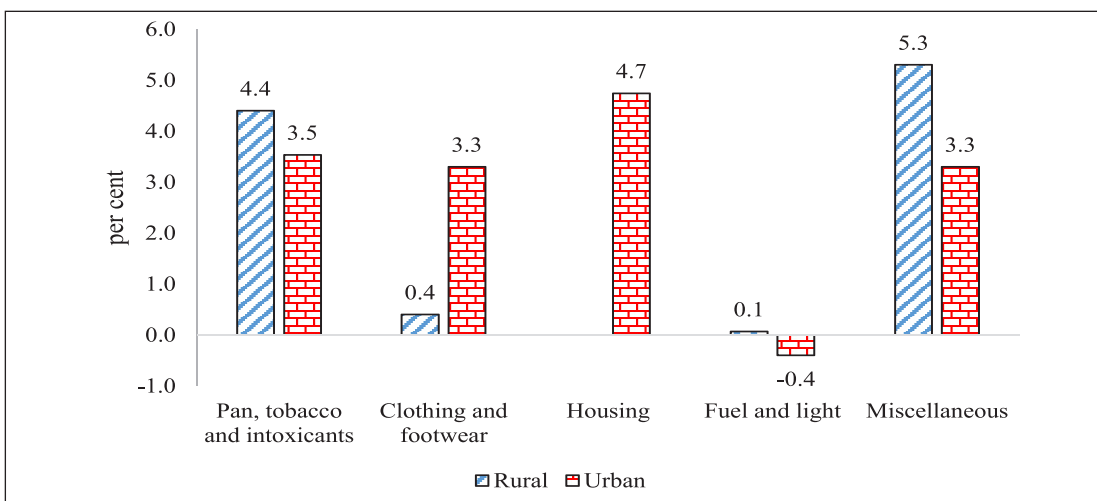
राज्यों में मुद्रा-स्फीति

5.8 (सीपीआई-सी) समेकित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राज्यों के स्तर पर अत्यधिक भिन्नता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 0.04 प्रतिशत से 8.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 1.3 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत के बीच में थी। परन्तु प्रायः सभी राज्यों में समग्र मुद्रा-स्फीति दर काफी कम रही। पंद्रह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुद्रा-स्फीति वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में 4 प्रतिशत नीचे थी। वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) की

वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि मुद्रा-स्फीति में वास्तविक आधार पर 15 राज्यों में गिरावट आई है। उन्नीस राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के अखिल भारतीय औसत की तुलना में मुद्रा-स्फीति दर कम थी जिसमें दमन एवं दीव की मुद्रा-स्फीति दर सबसे कम थी और उसके बाद बिहार और छत्तीसगढ़ में कम थी (चित्र 8)।

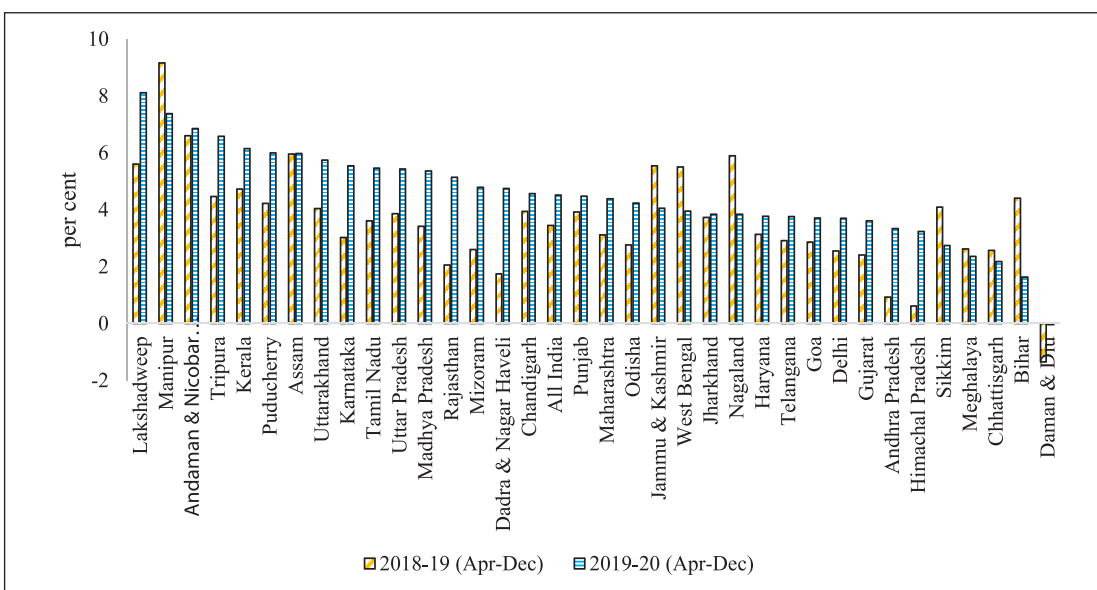
5.9 यद्यपि अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्रों की समग्र मुद्रास्फीति दर से कम है, सभी राज्यों में किसी विशेष माह में ग्रामीण मुद्रास्फीति समग्र विचरण पूरे राज्यों के शहरी मुद्रास्फीति की विचरण से अधिक थी। चित्र 8 में ग्रामीण और शहरी मुद्रा-स्फीति को चित्रित किया गया है जिसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण मुद्रास्फीति की विचरण शहरी मुद्रास्फीति की विचरण की तुलना में बहुत अधिक है। (चित्र 9 और 10)

चित्र-7: 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में घटक के अनुसार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति



स्रोत:- एन. एस. ओ.

चित्र 8: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीपीआई आधारित संयुक्त मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

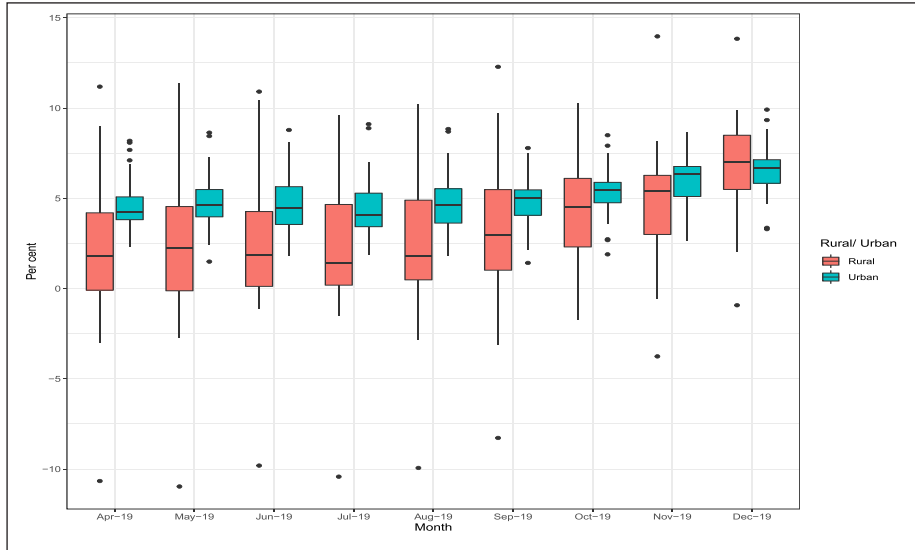


स्रोत:- एन. एस. ओ.

5.10 चित्र-3 और 9 ये दर्शाते हैं कि भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र मुद्रास्फीति अखिल भारतीय स्तर पर कम हो, परंतु सर्वत्र राज्यों में उच्च भिन्नता के कारण कुछ राज्यों के पास ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की मुद्रास्फीति से अधिक हो सकती है। चित्र-10 यह

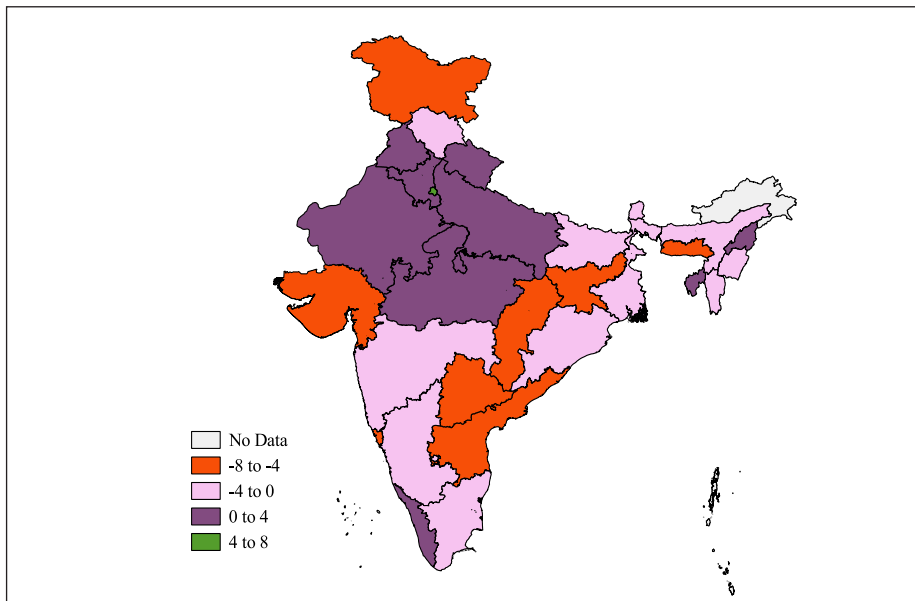
दर्शाता है कि पंजाब, उत्तराखंड, में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और केरल राज्य में ग्रामीण मुद्रास्फीति वस्तुतः अप्रैल-दिसम्बर, 2019 में शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी।

चित्र 9: वर्ष 2019-2020 (अप्रैल-दिसम्बर माह) में राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी मुद्रा-स्फीति में अंतर



स्रोत:- एन. एस. ओ.

चित्र 10: वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में राज्यों में सीपीआई मुद्रास्फीति



स्रोत:- एन. एस. ओ.

मुद्रास्फीति के कारक

5.11 वर्ष 2018-2019 के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का प्रमुख कारक, विविध समूह था। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में कुल मुद्रास्फीति में भोजन तथा पेय पदार्थों का योगदान कम था। (चित्र 11) हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर) में खाद्य पदार्थ (भोजन) तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे। इस अवधि के दौरान इन दोनों का मुद्रास्फीति में कुल 54% का योगदान रहा। इस अवधि के दौरान विविध समूह दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। (चित्र-12)

कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि

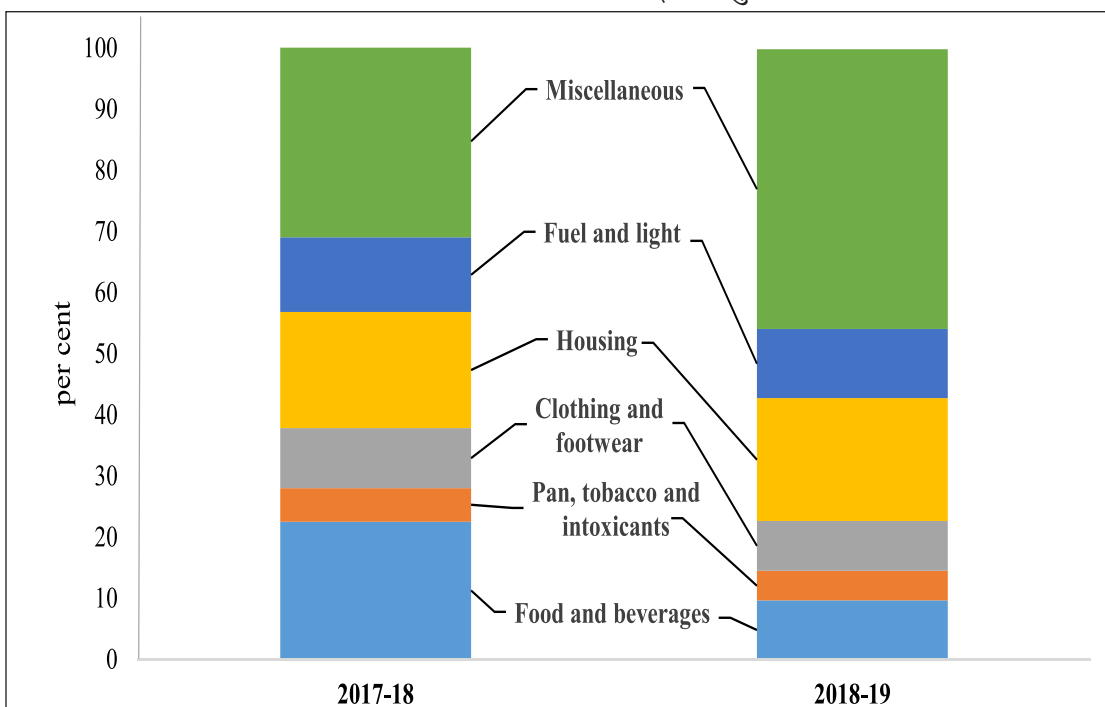
5.12 अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान वैश्विक स्तर पर कमजोर वैश्विक मांग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई थी। देश के आयात समूह में एक प्रमुख भाग होने के नाते इस मद का पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यू पी आई में खनिज तेल समूह में अप्रैल 2019 में 5.8% महंगाई दर देखी

गई तत्पश्चात दिसंबर 2019 में -3.2 तक की गिरावट दर्ज की गई। (चित्र 13) वास्तव में डब्ल्यू पी आई में यह समूह भारतीय कच्चा तेल समूह (इंडियन क्रूड बास्केट) में मूवमेंट की दिशा पर बारीकी से नजर रखता है। सीपीआई के ईंधन कारक/घटक भी इसी दिशा में ही मूवमेंट दर्शाते हैं। (चित्र 13)

दवा मूल्य निर्धारण

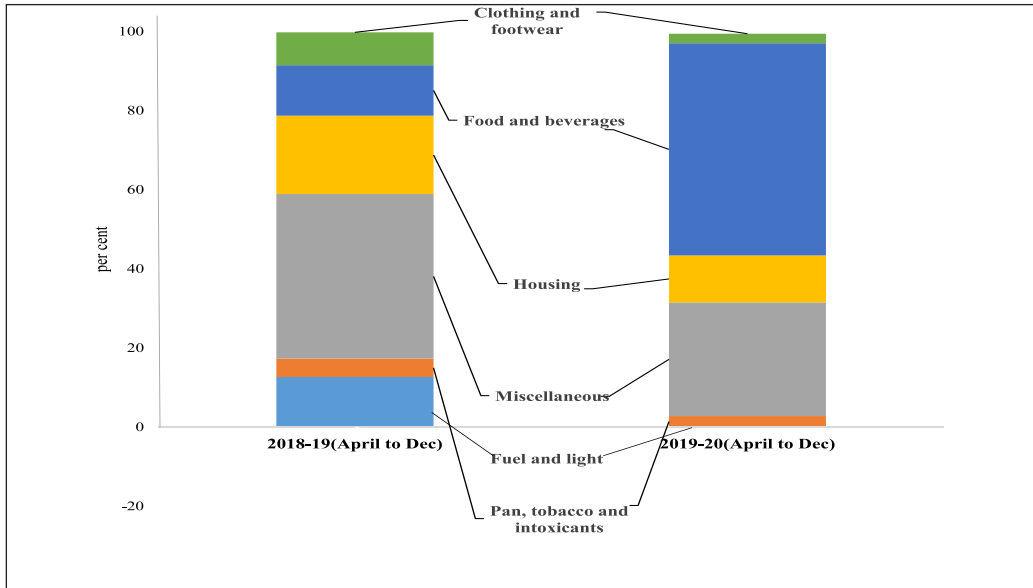
5.13 सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले कुल जेब खर्च में से, प्रमुख हिस्सा दवाओं पर ही खर्च होता है। यह सस्ती दवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र न केवल कल्याणकारी निहितार्थों के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वरन इसकी तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्थित के सिद्ध रिकॉर्ड के साथ एक क्षेत्र के रूप में इसका आर्थिक महत्व है। इस क्षेत्र में हाल ही के वर्षों के दौरान काफी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है तथा आने वाले वर्षों के दौरान इसमें और अधिक विकास की क्षमता भी है।

चित्र 11: 2017-18 से 2018-19 में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में योगदान



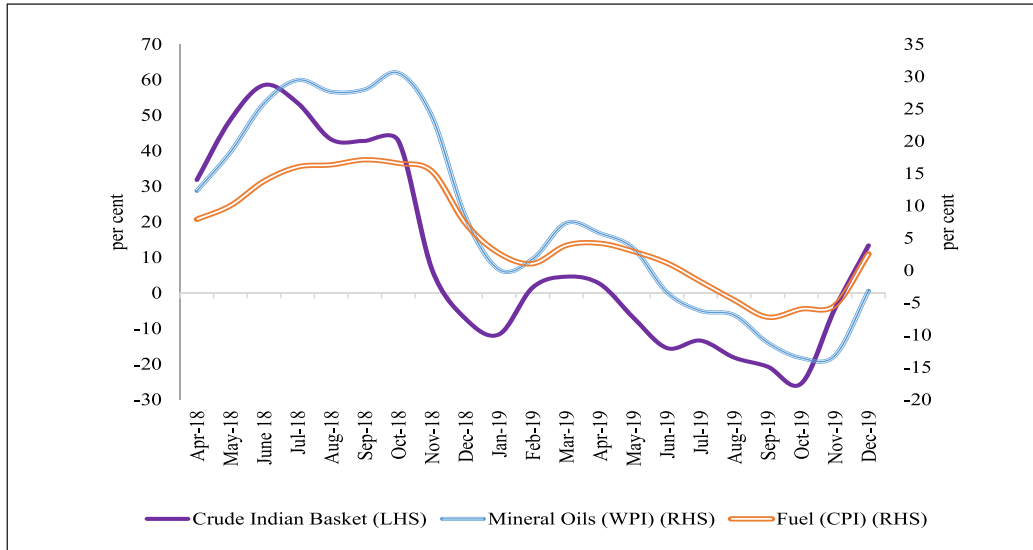
स्रोत: एनएसओ

चित्र 12: वर्ष 2018-19 (अप्रैल से दिसम्बर) तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (सी पी सी-आई) मुद्रास्फीति में योगदान



स्रोत:- एन. एस. ओ.

चित्र 13: भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत में साल दर साल वृद्धि, डब्ल्यूपीआई में खनिज तेलों तथा सीपीआई-सी में ईंधन में मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ से लिया गया सीपीआई डाटा, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से इंडियन क्रूड बास्केट की दर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डब्ल्यूपीआई डाटा ऑफिस, डीपीआईआईटी; सर्वेक्षण गणनाएँ।

नोट: सीपीआई में ईंधन में मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति की गणना-एलपीजी, केरोसिन, डीजल, अन्य फ्युल, वाहनों के लिए पेट्रोल, वाहन के लिए डीजल तथा अन्य वाहनों के लिए अन्य इंधनों के आधार पर की गई है।

5.14 सरकार आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण नीति, 2012 लेकर आई

ताकि जरूरी दवाओं- “अत्यावश्यक दवाईयों”- की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए नवाचार और

प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके जिससे रोजगार के लक्ष्य भी पूर्ण हों और सभी का साझा आर्थिक कल्याण हो सके।

5.15 आवश्यक दवाओं और औषधियों को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम) के अंतर्गत रखते हुए डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया और फिर मूल्य नियंत्रण के तहत लाया गया। एनपीपीए ने दिसम्बर, 2019 तक की पहली अनुसूची में शामिल दवाओं के 860 फॉर्मूलेशन/पैक्स की उच्चतर कीमतें तय की हैं। एनएलईएम 2015 तैयार करने के लिए डीओपीसीओ 2013 की घोषणा से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ 2013 के तहत आने वाले निर्धारित फॉर्मूलेशन/सूत्रण की कीमतों में कमी का विवरण तालिका 5 में दिखाया गया है।

5.16 उच्चतम मूल्य/अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) के निर्धारण से डी पी सी ओ 2013 के कार्यान्वयन के उपरांत जनता को कुल ₹12,447 करोड़ की बचत हुई। इसमें कोरोनरी स्टेंट उच्चतम मूल्य के निर्धारण से ₹ 4,547 करोड़, (नी इंफ्लान्टेशन) घुटना पत्यारोपण के मूल्य के निर्धारण के लिए ₹ 1500 करोड़

और कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टी एम आर) के लिए ₹ 984 करोड़ की बचत शामिल है।

5.17 कार्डिएक स्टेंट के मामले में पोस्ट मूल्य कैपिंग अवधि (2017) दो वर्ष से अधिक अवधि के बाद यह देखा गया कि भारत के बाजार में इस कार्डिएक स्टेंट की बिक्री में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह भी पाया गया कि भारतीय निर्माताओं को कार्डिएक स्टेंट की मूल्य कैपिंग से लाभ हुआ क्योंकि उत्पादन में इनकी भागेदारी में उत्तर मूल्य कैपिंग अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

खाद्य स्फीति (महंगाई)

5.18 जैसा कि पैरा में 5.3 चर्चा की गई है, खाद्य महंगाई की कुल महंगाई में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य भूमिका है। कुछ जिन्स यथा प्याज, टमाटर और दालों में अगस्त 2019 से बहुत अधिक महंगाई हुई है बेमौसम वर्षा के कारण कम उत्पादन हुआ और साथ ही साथ प्याज टमाटर की बाजार में कम आपूर्ति हुई। दालों के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई बहुत कम स्तर की हुई।

तालिका 4: डीपीसीओ, 2013 की घोषणा से पूर्व प्रचलित उच्चतम मूल्य के संबंध में अधिसूचित फॉर्मूलेशन/सूत्रण के अधिकतम मूल्य में कमी की रेंज/सीमा दर्शाता विवरण।

अधिकतम मूल्य में संबंध में % कटौती नियमन	एन एल ई एम 2015 में नियमन
0<= 5%*	236
5<=10%	138
10<=15%	98
15<=20%	100
20<=25%	92
25<=30%	65
30<=35%	46
35<=40%	26
40% से अधिक	59
Total formulations in NLEM 2015	860

स्रोत: एनपीपीए; फार्मासूटिकल विभाग

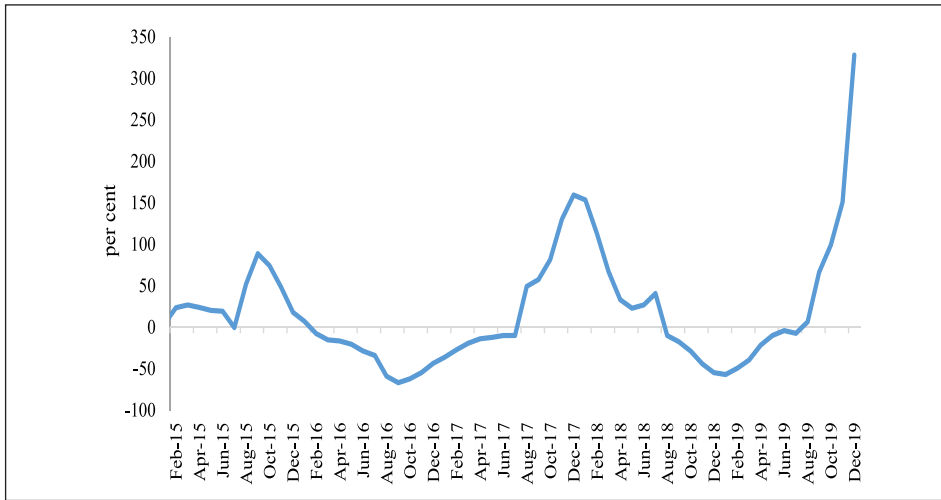
(क) प्याज

5.19 प्याज की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर में अप्रैल 2019 से बढ़ोत्तरी का रुझान दिख रहा है और वर्ष दर वर्ष आधार पर दिसंबर 2018 की तुलना में दिसंबर, 2019 के माह को दौरान 328.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई (चित्र 14)। दिसंबर,

2019 के माह के दौरान प्याज की डब्ल्यू.पी.आई. आधारित मुद्रास्थिति दर में वर्ष आधार पर दिसम्बर, 2018 में (-)63.8 की गिरावट की तुलना में 455.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी हुई।

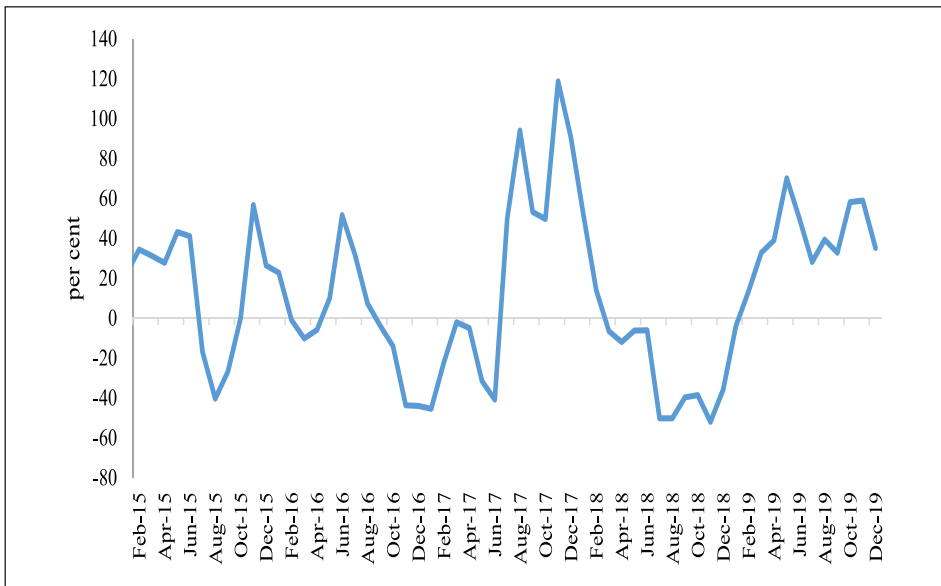
5.20 प्याज की मूल्य वृद्धि के बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष देखे जाने वाला एक प्रारंभिक कारण

चित्र-14: 2015-2019 के दौरान प्याज की महीनेवार उपभोक्ता सूचकांक (संयुक्त) के अनुसार महंगाई दर (प्रतिशत)



स्रोत:- एन. एस. ओ.

चित्र-15: टमाटर की महंगाई दर में सीपीआई (संयुक्त) में महीनेवार रुझान 2015-2019 के दौरान (नवंबर तक)



स्रोत:- एन. एस. ओ.

तालिका-5 भारत में प्याज की आगत

साह	All India Arrivals (in Lakh Tonnes)		
	पांच साल का औसत (2013-2017)	2018	2019
जनवरी	12.9	11.1	13.0
फरवरी	10.5	11.0	13.6
मार्च	9.9	9.5	12.0
अप्रैल	10.0	8.9	12.8
मई	11.6	12.5	11.6
जून	10.5	12.9	13.5
जुलाई	8.0	9.8	11.0
अगस्त	7.2	10.3	10.0
सितंबर	7.1	10.0	7.4
अक्टूबर	8.0	10.8	7.4
नवंबर	8.7	8.3	6.1
दिसंबर	11.1	10.6	N.A.

स्रोत: मासिक रिपोर्ट प्याज, नवंबर 2019, बागवानी सांख्यिकी विभाग

मांग-आपूर्ति में असंतुलन है जो मूल रूप से मौसम की वजह से हो सकता है। इस मांग और आपूर्ति के असंतुलन को और अधिक बढ़ाने के अन्य कारणों में दर्शाए बोआई क्षेत्र में गिरावट और बरसात की वजह से खरीफ प्याज की क्षति होना है। जैसे कि खरीफ उत्पादक राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान) ने सूचित किया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 प्रतिशत कम बुवाई/प्रतिरूपण है। खरीफ प्याज की फसल की क्षति का कारण सितम्बर-अक्टूबर 2019 में भारी बारिश भी है (जैसा कि बागवानी राज्य निदेशालय द्वारा सूचित किया गया मध्य प्रदेश में (58 प्रतिशत), कर्नाटक में (18 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश में (2 प्रतिशत) की क्षति हुई। महाराष्ट्र में फसल उपज के लिए तैयार थी किंतु बारिश के कारण के कारण इसमें विलंब हुआ जैसा कि जुलाई से नवंबर 2019 के महीनों के दौरान बाजार में प्याज की कम आगत से पता चलता है (तालिका 5)

(ख) टमाटर

5.21 बोए गए टमाटर की सीपीआई के आधार पर महंगाई दर में जुलाई 2019 से वृद्धि का रुझान देखा गया और यह वृद्धि वर्ष दर वर्ष के अनुसार दिसंबर, 2018 की तुलना में दिसम्बर 2019 के दौरान 35.2 प्रतिशत तक थी। (चित्र 15)

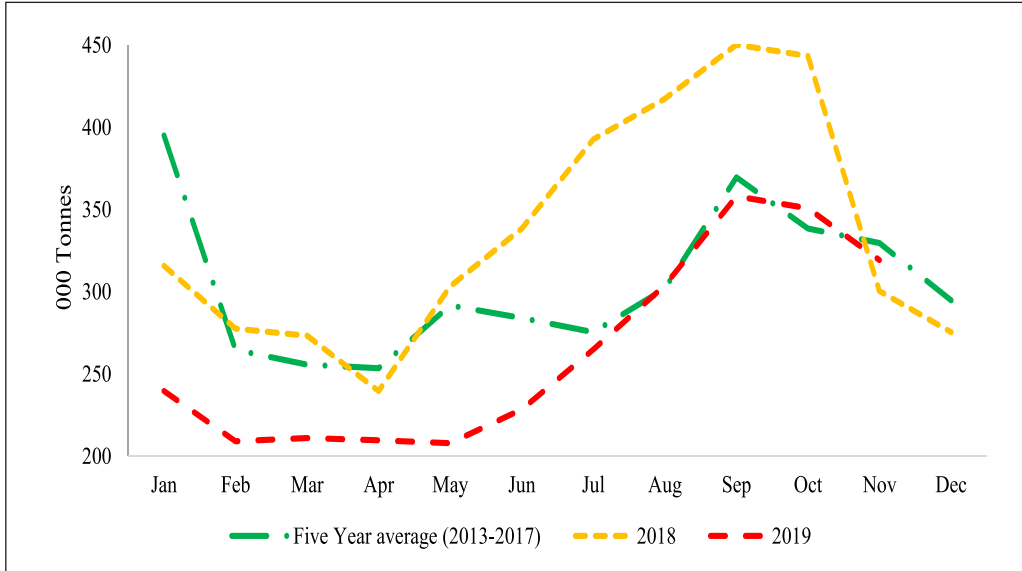
5.22 जुलाई-दिसंबर 2019 के दौरान टमाटर की कीमत वृद्धि 2017 के दौरान देखी गई वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। 2019 में टमाटर की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में अधिक वर्षा के कारण है जो कि टमाटर के मुख्य उत्पादक राज्य है। इस प्रकार टमाटर की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। नवम्बर 2019 में बाजार में टमाटर की आगत अक्टूबर 2019 से कम है और पिछले पांच वर्ष (2013-17) वर्ष की औसत से भी कम है। किन्तु यह पिछले वर्ष के इसी माह से कुछ अधिक

रही। बाजार में टमाटर की आपूर्ति में विसंगति के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। टमाटर की मासिक अखिल भारतीय आगत नीचे चित्र 16 में दी गई है:-

(ग) दालें

5.23 दालों की डब्ल्यूपीआई महंगाई दर जनवरी 2018 के -20.2 प्रतिशत तुलना में दिसंबर 2019

चित्र 16- महीनेवार टमाटर की भारत में आगत



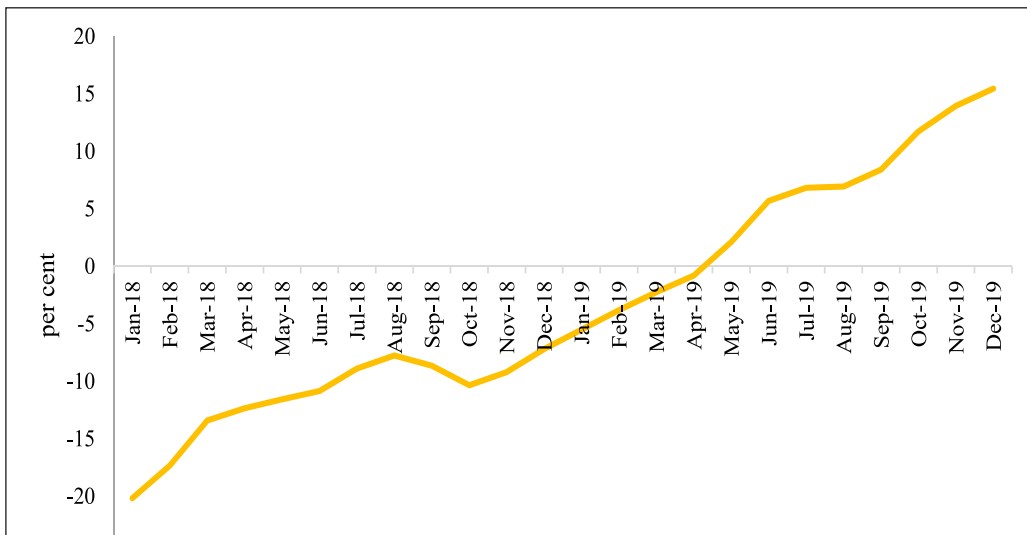
स्रोत - एगमार्केटनेट, कृषि मंत्रालय, निगम और कृषक कल्याण

में 15.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर समग्र महंगाई दर दिसंबर 2018 के दौरान (-) 7.2 प्रतिशत की तुलना में दालों के संबंध में दिसंबर 2019 के दौरान

15.4 प्रतिशत रही।

5.24 तथापि मदवार दालों की महंगाई दर का रुख यह प्रकट करती है कि विभिन्न दालों के मूल्यों में वर्तमान

चित्र 17: सीपीआई आधारित दालों में मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)



स्रोत:- एन. एस. ओ.

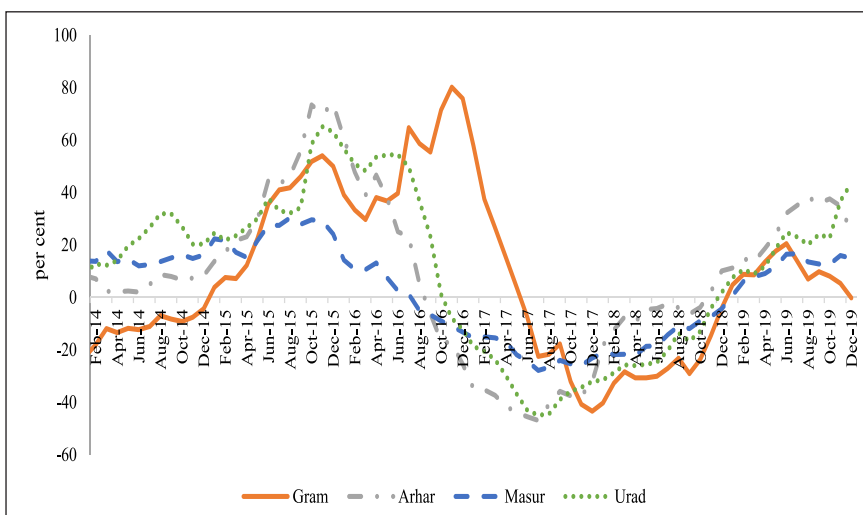
वृद्धि इनके दीर्घकालिक प्रवृत्ति की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। (चित्र 18)

5.25 2019 से कीमतों में वृद्धि का दौर के कारणों में-उगाने वाले राज्यों में बुवाई क्षेत्रों में कमी, पिछले साल पैदावार के आधिक्य से मूल्यों में कम वसूली हो सकती है। यह ध्यान रखा जाए कि दालों का उत्पादन वर्ष, 2015-2016 में 163.5 मिलियन टन से बढ़ कर 2016-2017 में 231.3 मिलियन टन बढ़ा

- एक वर्ष की अवधि में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 और 2016-17 (चित्र 19) में 298 लाख हैक्टेयर और 294 लाख हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 2018-19 में औसत सीमान्त घटकर 290 लाख हैक्टेयर हो गयी है। 2018-2019 के दौरान कम बाजार मूल्य के परिणामस्वरूप कुछ दालों की बुवाई में कमी हो सकती है।

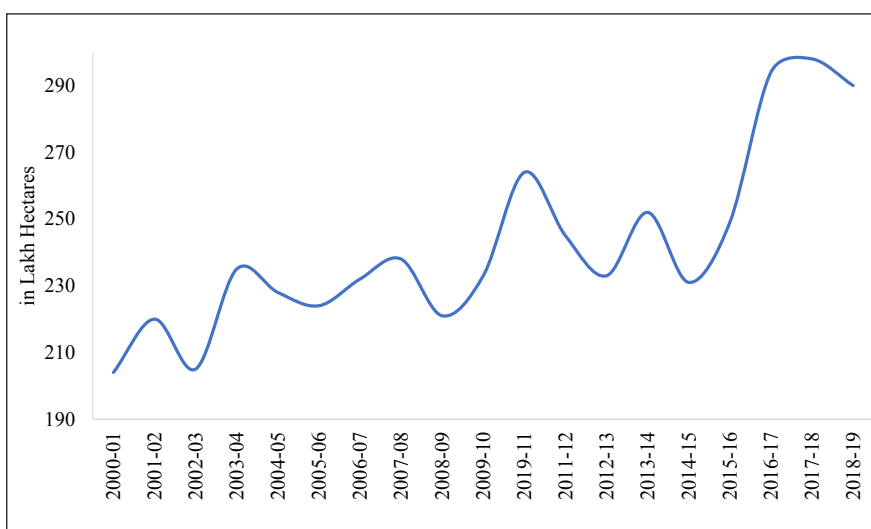
5.26 दालों का उत्पादन जिसमें 2015-2016 तक

चित्र 18: डब्ल्यूपीआई के आधार पर दालों की महंगाई दर (प्रतिशत में)



स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यक्रम, डीपीआईआईटी कृषि संख्यकों की पॉकेट बुक, कृषि और कृषक

चित्र 19: भारत में दालों के अंतर्गत क्षेत्र



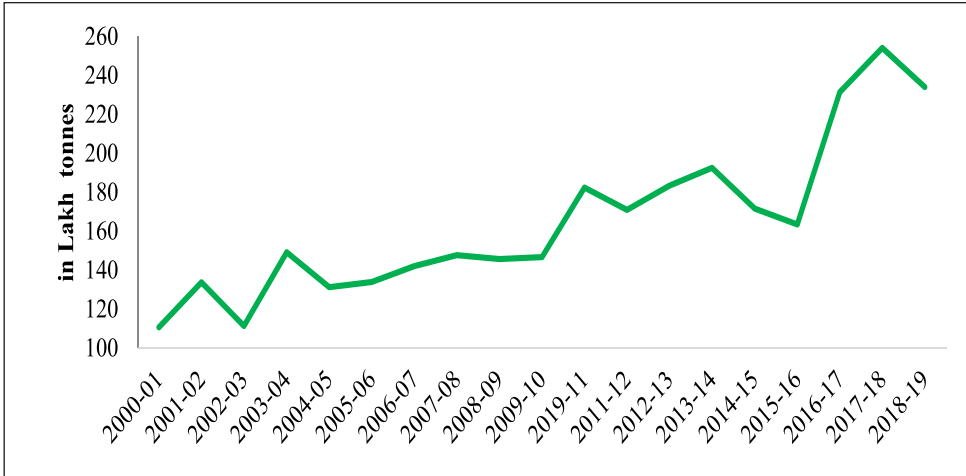
स्रोत: कृषि सांख्यिकि पाकेट बुक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

निरंतर बढ़ोत्तरी हुई थी, वर्ष 2017-18 से 2018-19 से निरंतर कमी दिखाई देती है पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान 7.9 प्रतिशत की कमी रही।

(चित्र-20)

बाक्स 1 दालों में मकड़ जाल की विद्यमता की संभावना के लिए जांच का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

चित्र 20 भारत में दालों का उत्पादन (लाख टन में)



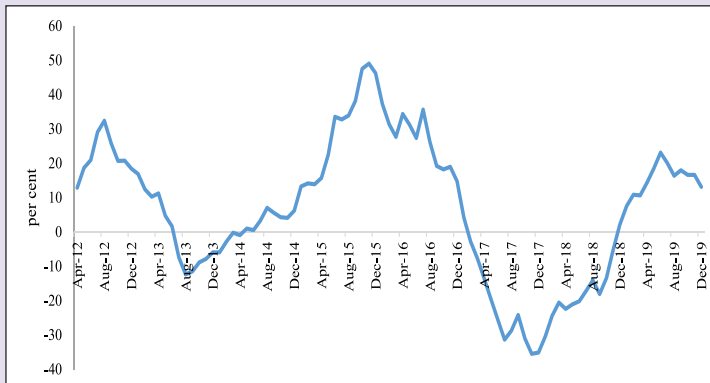
स्रोत कृषि सांख्यिकी पॉकेट बुक, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय

बॉक्स 1: दालों में मकड़ जाल

मकड़ जाल का सिद्धांत एक विचार है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव आपूर्ति में उतार चढ़ाव कर सकता है, जिसकी वजह से मूल्यों में बढ़ोत्तरी और गिरावट की क्रम बनता है। किसान उस समय मकड़ जाल के घटना क्रम में फस जाते हैं। जब वे अपनी फसल की बुवाई गत वर्ष की बजार अवस्था अवधि के आधार पर करने का निर्णय लेते हैं। अतः किसान किसी 'टी-1' अवधि के दौरान किसी फसल विशेष के लिए उच्च मूल्य देखता है तो वह 'टी' अवधि के दौरान इसकी अधिक पैदावार करने की सोचता है। तथापि यदि इसका उत्पादन बाजार की मांग से अधिक हो जाता है तो अवधि 'टी' में मूल्य में गिरावट हो जाती है, किसानों को संकेत जाता है कि अवधि -टी+1' में इस उत्पाद का कम उत्पादन किया जाए।

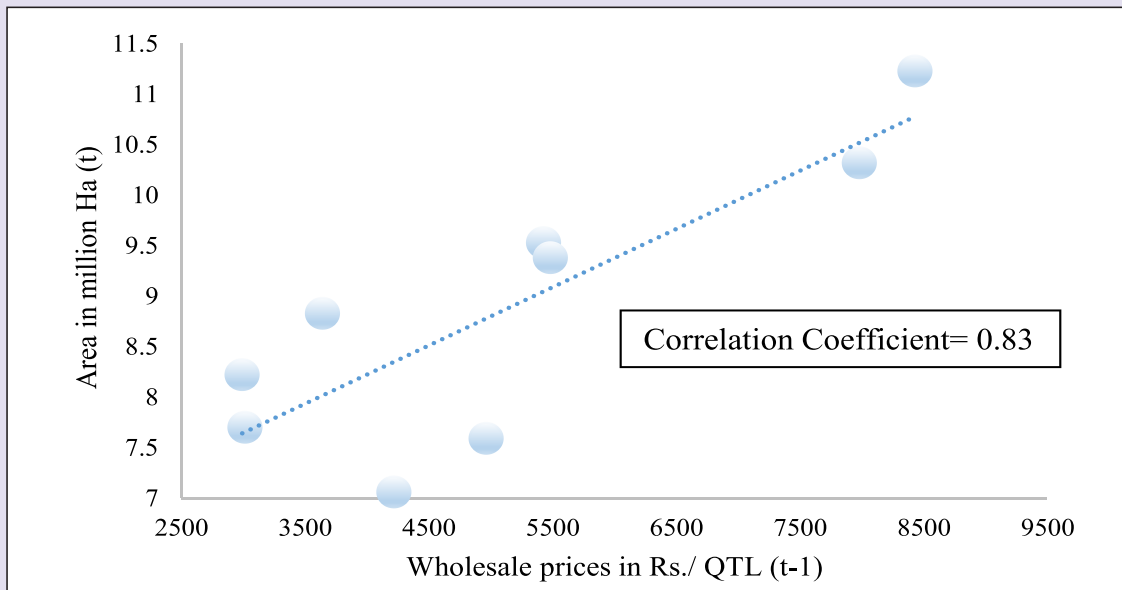
नीचे दिया गया आंकड़ा दलहन की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है। कमी और वृद्धि दोनों ही मामलों में उच्चता देखी गई है। वर्तमान उच्चता वर्ष 2015-16 में देखी गई उच्चता की तुलना में कम है। वर्तमान उच्चता दलहन में मौजूद मकड़जाल की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है।

अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2019 तक दलहन का डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति दर



स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

अवधि (टी-1) में दाल के थोक मूल्य और अवधि t में बुआई क्षेत्रों के बीच संबंध

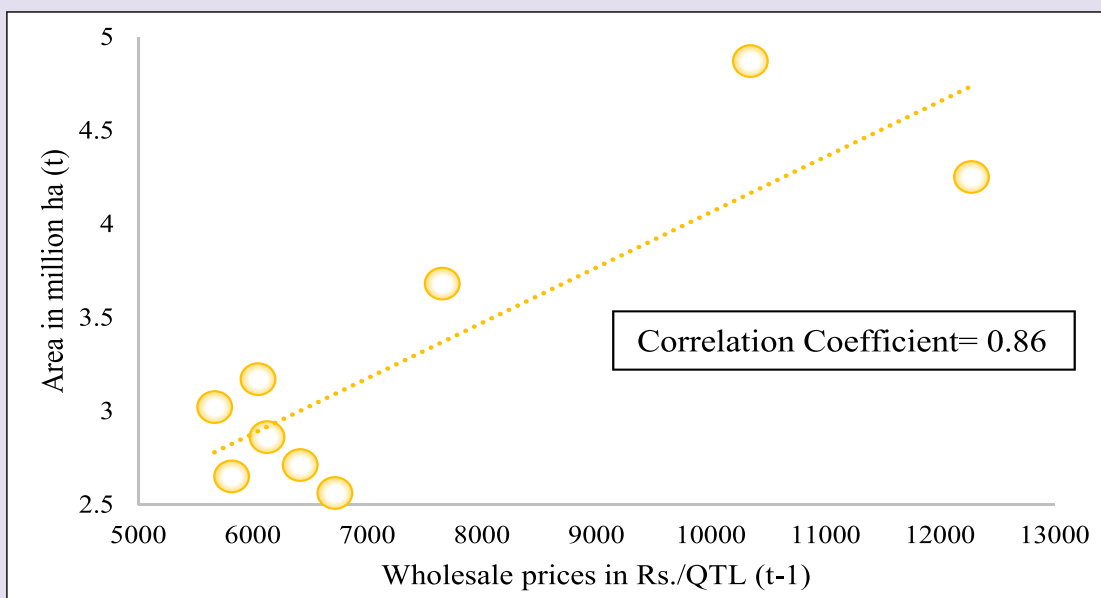


स्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग एवं कृषि मंत्रालय

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए चना, अरहर उड़द और मूंग के संबंध में बुवाई और थोक मूल्यों का विश्लेषण। अवधि 'टी' में बोया गया क्षेत्र अवधि 'टी-1' के थोकविक्रय मूल्य पर विचार किया जाता है। उपरोक्त आंकड़ा अवधि टी-1 में थोक मूल्यों और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक दो चर के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापता है। चना के मामले में सहसंबंध गुणांक 0.83 होता है।

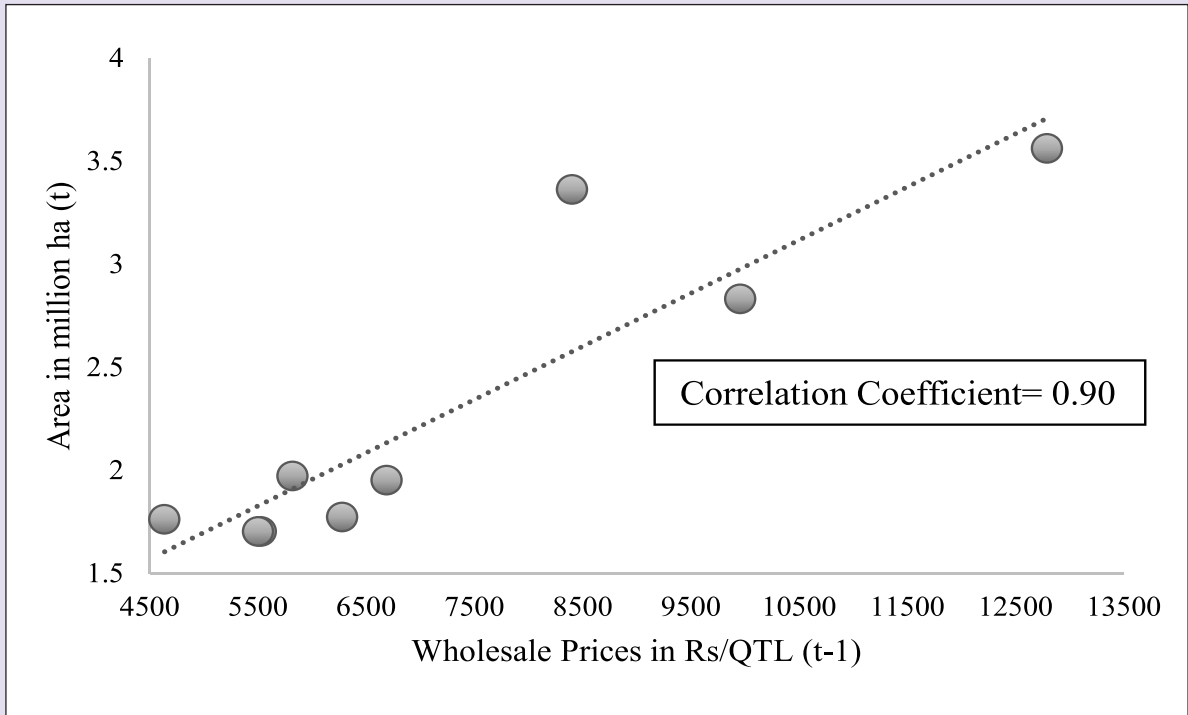
चना के मामले में भी, दो चर के बीच संबंध सकारात्मक है और सहसंबंध गुणांक के मूल्य के अनुसार अधिक मजबूत (0.86) है।

(टी-1) अवधि और अवधि टी में चने के थोक मूल्य के मध्य संबंध



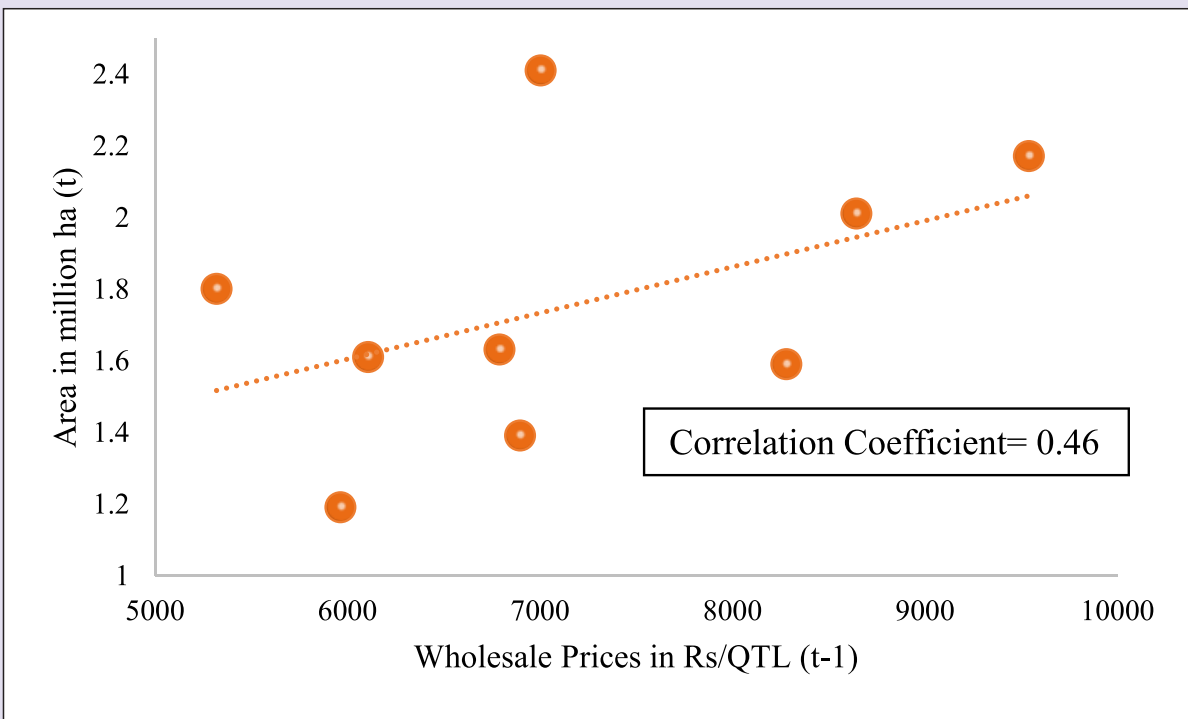
स्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग और कृषि मंत्रालय

अवधि (टी-1) में उड़द के थोक मूल्य और और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच संबंध



स्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग एवं कृषि, मंत्रालय

अवधि (टी-1) में मूंग के थोक मूल्य और और अवधि टी में बोए गए क्षेत्र के बीच संबंध



स्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता कार्य विभाग और कृषि मंत्रालय

उड़द के संदर्भ में भी धनात्मक संबंध है और सहसंबंध गुणांक 0.90 है। मूँग के लिए भी इसी तरह की सकारात्मक संगति देखी गई थी। तथापि मूँग के मामले में सहसंबंध गुणांक अनुपातिक रूप से 0.46 पर कम रहा।

मकड़तंत्र की स्थिति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा उपायों के अलावा किसानों द्वारा दलहन को खराब/कीमत आघात से होने से बचाने के लिए तथा सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे जो इस प्रकार हैं: मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दखल, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत कवरेज, पी एम-आशा, गोदाम उपलब्ध कराना, परिवहन में सुधार, ई-एनएएम आदि के माध्यम से कीमतों की पड़ताल करना, भारत को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए दालों के निःशुल्क निर्यात को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

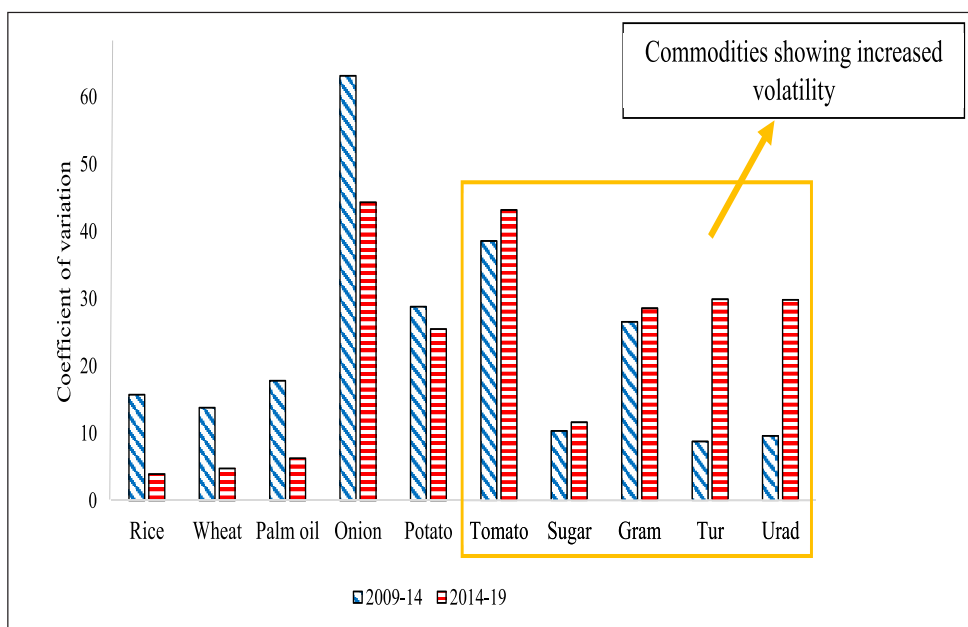
शोधों से यह भी पाता चलता है कि सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद की स्थिति मजबूत करने, बाहरी व्यापार का विस्तार बढ़ाने, मूल्यों के स्तरीकरण, किसानों हेतु यातायात लागतों में कमी करना जिसके लिए उन्हें बेहतर सड़कों और प्रभावशाली बाजार चैनलों से जोड़ा जाएगा ताकि उत्पादन साथ ही साथ दालों की निवल डपलब्धता बढ़ सके और इस प्रकार दालों की आपूर्ति में सुधार लाया जा सके (क्रिसिल, 2017)।

विभिन्न अतिआवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण

5.27 दो समयावधि अर्थात वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान किया गया था। परिवर्तनशीलता को मापने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया गया है। यह आंकड़ों के इसके मध्य बिन्दु से प्रकीर्णन की एक सांख्यिकीय माप करता है। चावल और गेहूँ की कीमतें पर्याप्त घरेलू उत्पादन से और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

चावल और गेहूँ के पर्याप्त बफर स्टॉक के रख-रखाव के कारण आपूर्ति में वृद्धि होने से वर्ष 2014 तक स्थिर रहीं हैं। परिणामस्वरूप, कीमत में उतार-चढ़ाव चावल और गेहूँ के मामले में कम था (चित्र 21)। यह देखा जा सकता है कि समग्र कीमत उतार-चढ़ाव सब्जियों के लिए उच्चतम था और चावल, गेहूँ तथा खजूर तेल के लिए सबसे कम था। 2014-2019 के दौरान दाल, चीनी और टमाटर के लिए कीमत उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण वृद्धि थी।

चित्र 21: विविध आवश्यक कृषि वस्तुओं के परिवर्तन का गुणांक



स्रोत: पीएमसी, उपभोक्ता मामले विभाग

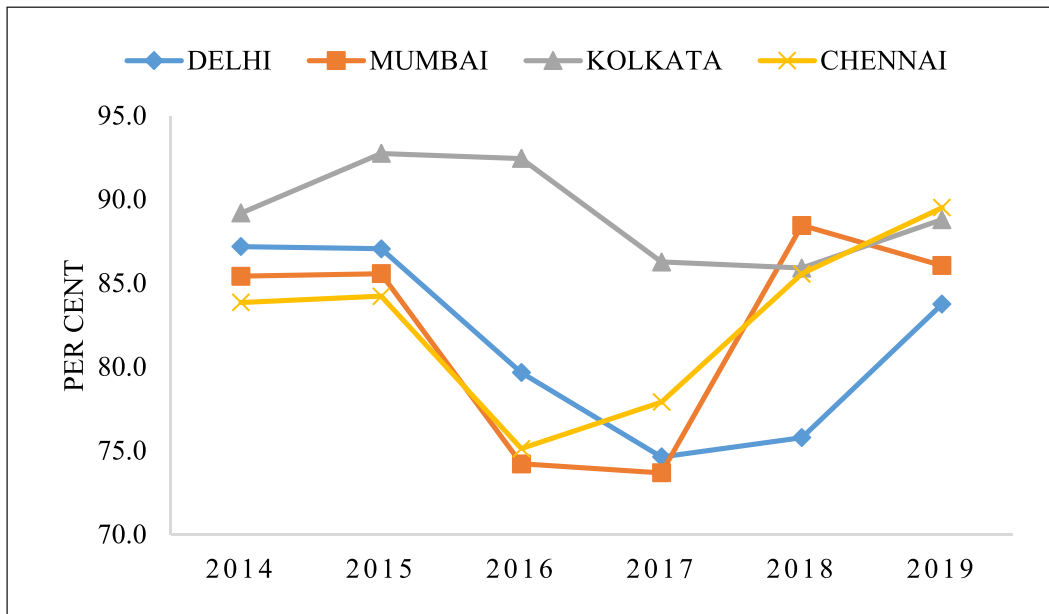
5.28 वह परिमाण जिस पर उत्पादन और खपत बुरी तरह प्रभावित होती है, कीमत में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है, जो कि आपूर्ति और मांग के लोच पर निर्भर करता है। स्टॉक धारण और अटकलबाजी का कीमत परिवर्तनशीलता पर, स्थायीकारी अथवा अस्थायीकारी भारी प्रभाव हो सकते हैं। वस्तुओं की नश्वरता भी कीमत उतार चढ़ाव में वृद्धि करती है। विपणन चैनलों की विद्यमानता, भंडारण सुविधाएं, प्रभावों एम एस पी प्रणाली भी कीमत उतार-चढ़ाव को सीमित करने में मददगार होती है।

कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों में अंतर

5.29 विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक बिक्री मूल्य में वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के दौरान देश के चार महा नगरों में अंतर देखा गया। प्रति कि.ग्रा. 10 से 15 प्रतिशत का मूल्य वैज, यदि हम बाजार लागतों और मार्जिनों (लाभांश) से इसकी तुलना करें, तो यह बहुत अधिक नहीं है। वर्ष 2019 में कुछ वस्तुओं के ये मार्जिन (लाभांश) अत्यधिक

है, और सभी वस्तुओं के मार्जिन दिल्ली और मुंबई में सबसे अधिक है। अरहर के मामले में मार्जिन (लाभांश) दिल्ली में 16 प्रतिशत प्रति कि. ग्रा. और मुंबई में 14 प्रतिशत प्रति कि. ग्रा. चना के मामले में, दिल्ली में मार्जिन प्रति कि. ग्रा. 28 प्रतिशत और मुंबई के मामले में प्रति कि. ग्रा. लगभग 20 प्रतिशत आता है। (चित्र 23)। मूंगफली तेल के मामले में, थोक बिक्री और खुदरा मूल्यों के बीच मार्जिन दिल्ली में लगभग 15 प्रतिशत था, जबकि कोलकाता और चेन्नई में मार्जिन 5-7 प्रतिशत था। मुंबई में मूंगफली तेल के मामले में मार्जिन सबसे अधिक 26 प्रतिशत था (चित्र 24)। सब्जियों के मामले में, दोनों प्याज और टमाटर के लिए कीमत वैज विश्लेषण किया गया है। दिल्ली एवं मुंबई में विशेष रूप से अधिक है। दिल्ली में यह मूल्य मार्जिन प्याज के लिए 51 प्रतिशत और टमाटर के मामले में यह 59 प्रतिशत था (चित्र 25 और 26) इसका निहितार्थ यह है कि मूल्यों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि उन सब्जियों के लिए अधिकतम है जो नष्ट होने के योग्य हैं और इसके बाद दालों के लिए है और खाद्य तेलों के लिए सबसे कम है।

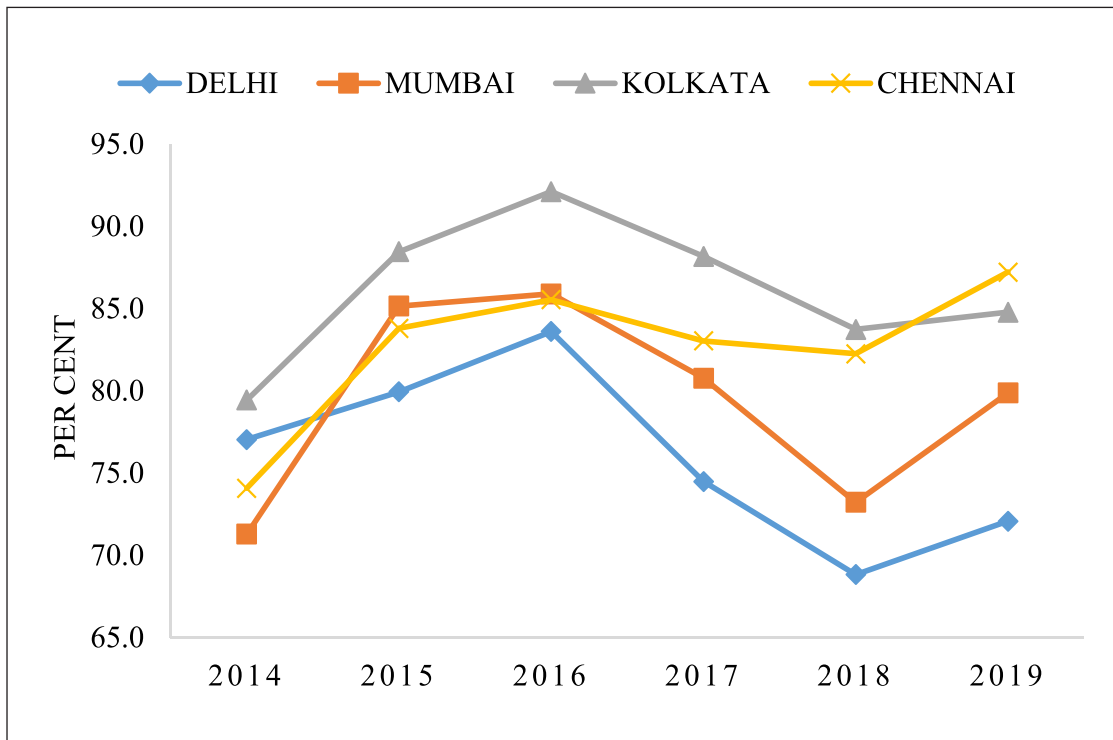
चित्र 22: अरहर के थोक और खुदरा मूल्यों का अनुपात



स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

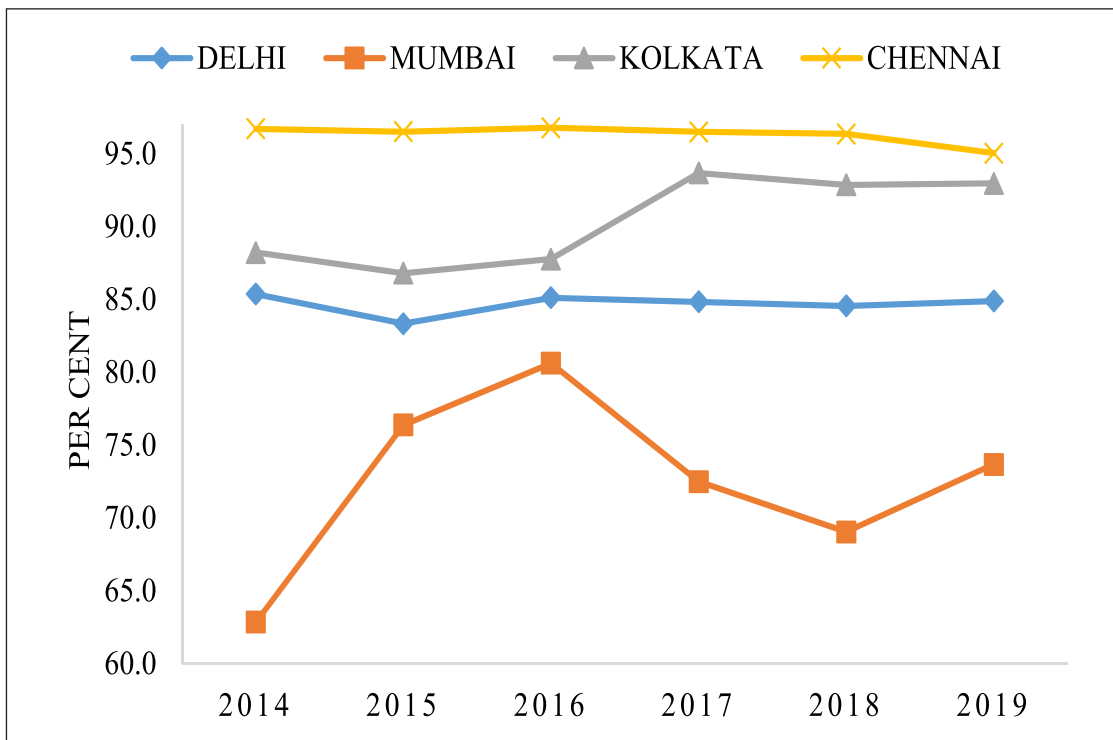
2. वैज $[1 - (\text{प्रति किलोग्राम थोक मूल्य} / \text{प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य})] * 100$

चित्र 23. चना का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात



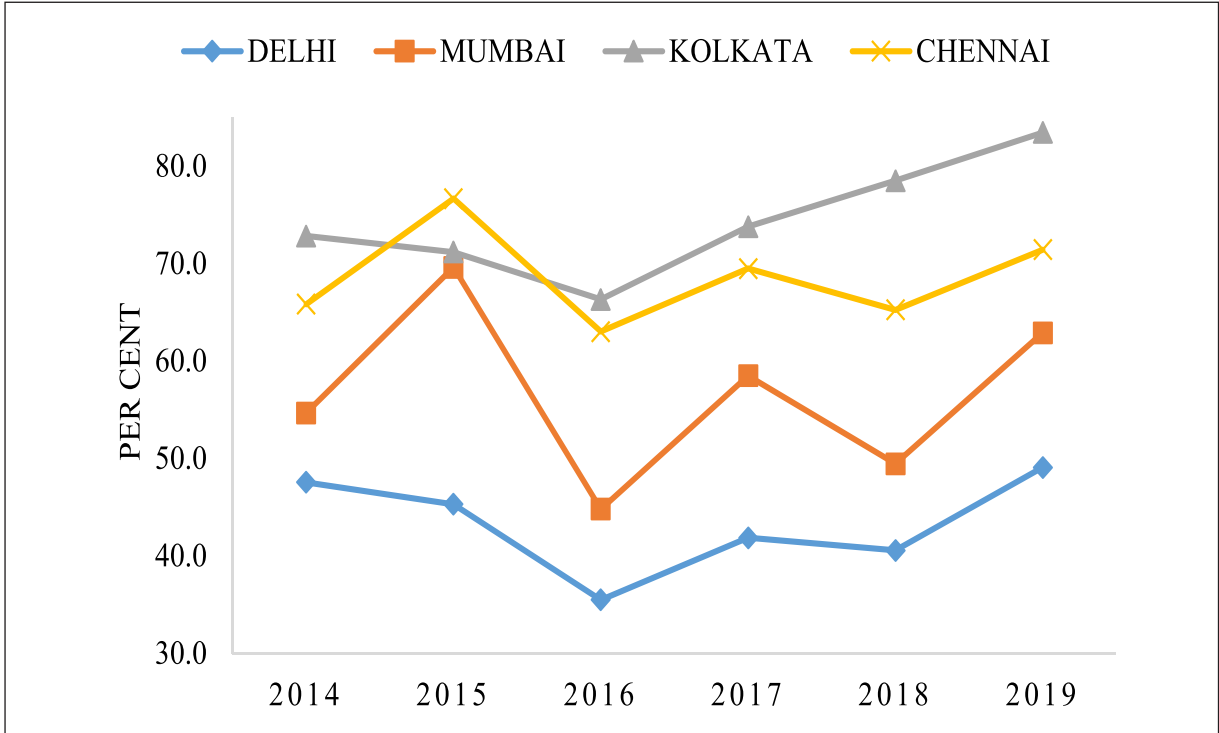
स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 24. मूंगफली तेल का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात



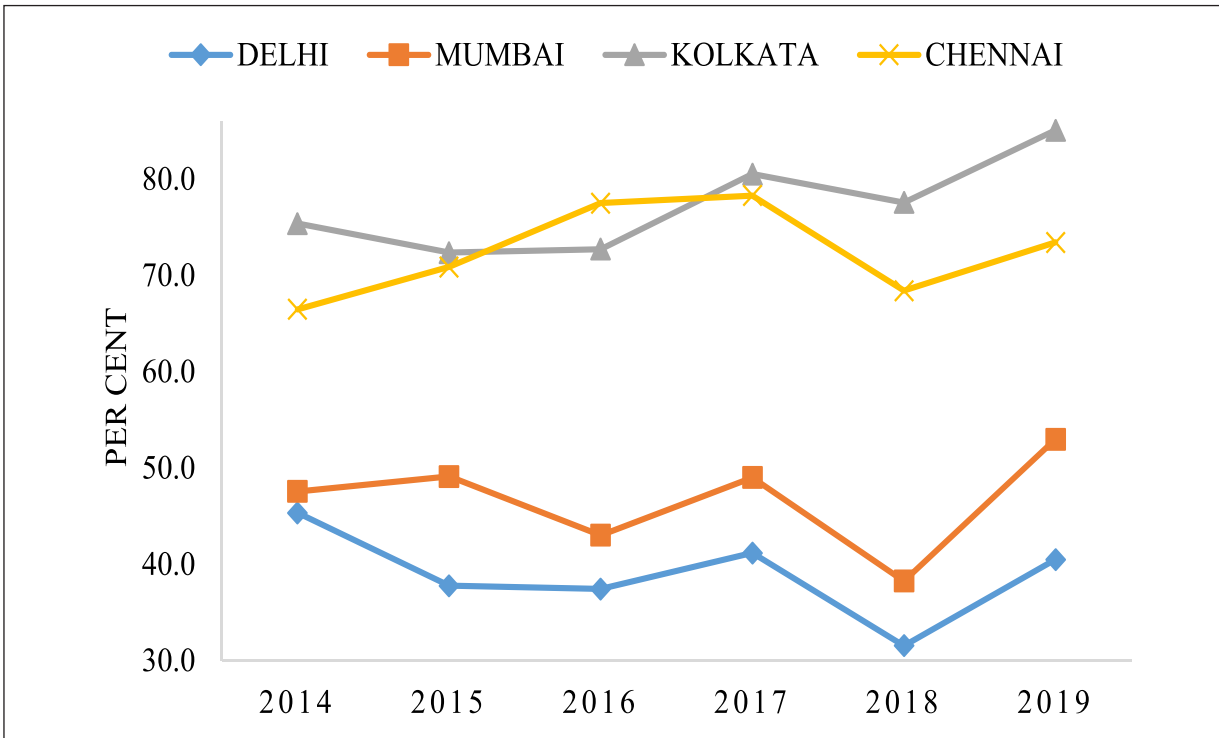
स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 25. प्याज का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात



स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

चित्र 26. टमाटर का थोक-खुदरा मूल्य दर अनुपात



स्रोत: पी एम सी, उपभोक्ता मामले विभाग

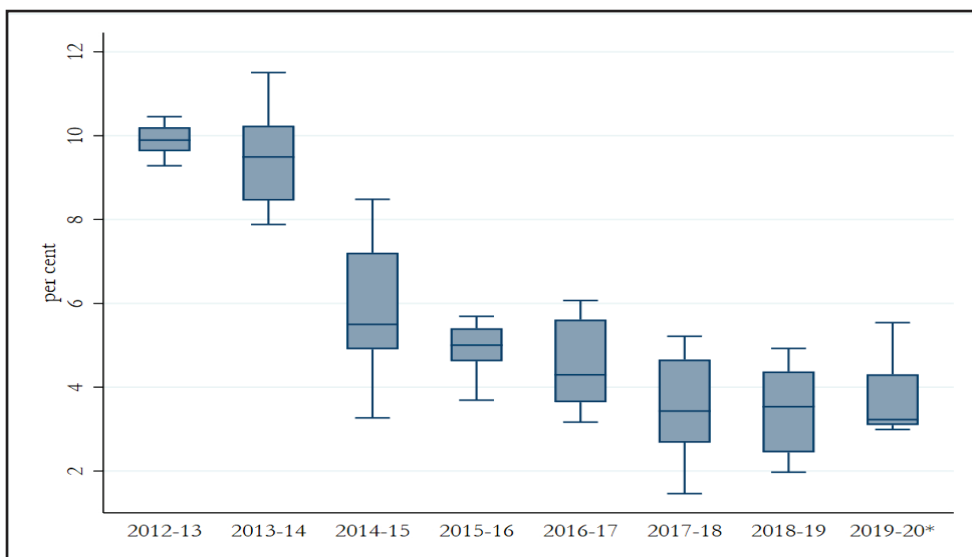
5.30 थोक एवं खुदरा मूल्यों के बीच इतने उच्च विस्तार के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं जिनमें मुख्य रूप से ऊंची लेनदेन लागतों, कमजोर अवसंरचना एवं सूचना प्रणालियों, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, मध्यस्थों के ऊंचे लाभांश, मध्यवर्तियों (बिचौलियों) की बड़ी संख्या में मौजूदगी, इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। यह एक तथ्य है कि देश के उत्तरी राज्यों में लेनदेन संबंधी लागते अन्य राज्यों की तुलना में उच्च हैं। (शर्मा और प्रमोद, 2001) विभिन्न राज्यों में बाजार संरचना भी भिन्न-भिन्न रूपों में है। यदि व्यापारियों के बीच पर्याप्त सीमा तक प्रतियोगिता हो तो प्राइस-वेज अधिक उच्च नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर, यदि व्यापारियों के बीच साठ-गांठ हो जाए तो प्राइस-वेज में अधिक उच्चता होगी। इसका एक अन्य कारण थोक से खुदरा और खुदरा से थोक कीमतों के कीमत संबंधी संकेतों के आदान-प्रदान में असंगति का हो सकता है और ऐसा मध्यवर्तियों की कार्रवाइयों के कारण हो सकता है। इसलिए, इस प्राइस-वेज को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार

की रुकावटों को तथा प्रणाली में लेनदेन लागतों को बढ़ाने वाली संरचनात्मक सख्तियों को हटाया जाए।

क्या महंगाई की गति में कोई बदलाव रहा है?

5.31 जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा 5.3 में चर्चा की गई है, वर्ष 2012-13 के दौरान महंगाई के उच्च स्तरों को देखने के बाद, सीपीआई-सी मूल्यवृद्धि वर्ष 2013-14 में नीचे आई तथा वर्ष 2014-15 और उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट हुई। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति (मूल्यावृद्धि) की गिरावट की वजह से यह प्रश्न उठता है कि क्या मुद्रास्फीति प्रक्रिया में कोई बदलाव है? चित्र 27 में, वर्ष 2012-13 से 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की अवधियों के संबंध में सीपीआई-सी सीरीज के लिए वित्त वर्ष-वार बॉक्स-प्लॉट² दर्शाए गए हैं। इस अविध के दौरान मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) के औसत स्तरों में पर्याप्त गिरावट हुई है। न केवल मुद्रास्फीति के औसत स्तरों में गिरावट हुई है बल्कि वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के चरम स्तर भी अब काफी नीचे हैं।

चित्र 27: वर्ष 2012-13 से 2019-20* सीपीआई-सी मूल्यवृद्धि का वितरण



स्रोत: परिकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सीपीआई-सी आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी*: वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के संगत है।

2 बॉक्स एवं व्हिस्कर प्लॉट हमें किसी वितरण की विशेषताओं का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। बॉक्स उस अंतर-चतुर्थक विस्तार को दर्शाता है जोकि वितरण पर 75वें बिंदु हैं। बॉक्स में क्षैतिज रेखा वितरण की माध्यिका का संकेत करती है तथा व्हिस्कर ऐसी रेखाएं हैं जो बॉक्स से अधिकतम और न्यूनतम मानों तक जाती हैं।

5.32 सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत में खाद्य तथा ईंधन महंगाई के जोरदार द्वितीयक प्रभाव पड़ें हैं जिनके कारण घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) संबंधी पूर्वानुमान बने रहे हैं। इससे मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और इसीलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति (महंगाई) पर प्रभाव बने रहते हैं (आनंद एवं अन्य, 2014; राज एवं मिश्रा, 2011)। खाद्य तथा ईंधन महंगाई के अतिरिक्त प्रभावों की उपस्थिति की जांच करने का एक तरीका उस तेजी का अवलोकन करना है जिसके कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति (महंगाई) खाद्य या ईंधन की कीमतों में किसी आघात के बाद मूल मुद्रास्फीति में रूपांतरित हो जाती है। यदि हेडलाइन मुद्रास्फीति एक सम्यक् अल्प समयावधि के भीतर मूल मुद्रास्फीति की ओर पूर्णतः अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटती है तो

$$\pi_t^{Headline} - \pi_{t-12}^{Headline} = \alpha_1 + \beta_1(\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}) + e_t$$

where, $\pi_t^{Headline}$ is the headline CPI-C inflation at time point t , $\pi_{t-12}^{Headline}$ is the headline CPI-C inflation 12 months prior to t and π_{t-12}^{Core} is the core inflation 12 months prior to t .

जनवरी, 2012 और नवंबर, 2019 के बीच, मासिक सीपीआई-सी मुद्रास्फीति आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन के लिए हम सामान्य रूप से प्रयुक्त निम्नलिखित समीकरण का प्राक्कलन करते हैं-

5.34 ये परिणाम (तालिका 6 और चित्र 28) संकेत करते हैं कि विचारित अवधि में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में दृढ़ प्रत्यावर्तन का प्रमाण मौजूद है। इस अवधि के लिए प्रतिगमन का ढाल गुणात्मक है और -1 के निकट है, जो 12 माह की अवधि के

यह जोरदार द्वितीयक प्रभावों का संकेत हो सकता है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन किसी स्फीति-लक्षक फ्रेमवर्क की दिशा में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निहितार्थ रखता है। जोरदार द्वितीयक प्रभावों से युक्त किसी अर्थव्यवस्था में, खाद्य या ईंधन की कीमतों में किसी आघात की स्थिति में, मौद्रिक नीति को, किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तुलना में जहां ऐसे प्रभाव न्यूनतम होते हैं, अधिक सख्त किया जाना आवश्यक हो सकता है।

5.33 हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में रूपांतरण के संबंध में हम देखते हैं कि वर्ष 2012 से सीपीआई-सी आंकड़ों के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में रूपांतरण हो रहा है। हम

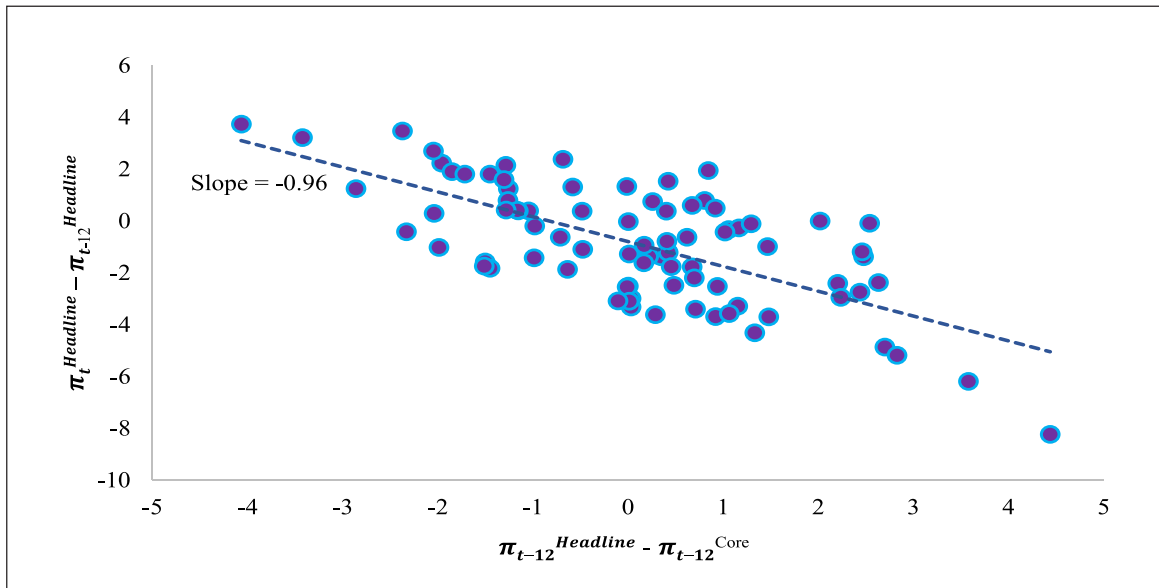
भीतर, हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में पूर्ण रूपांतरण का संकेत है। मूल मुद्रास्फीति के हेडलाइन मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन के बारे में किए गए परीक्षण के अंतर्गत समान प्रतिगमन के लिए समान प्रमाण उपलब्ध नहीं होते (तालिका 6)। इसका अभिप्राय यह है कि गैर-मूल अवयवों से मूल अवयवों पर पड़ने वाले द्वितीयक प्रभाव न्यूनतम हैं। इससे खाद्य और ईंधन की कीमत संबंधी आघात के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया के लिए निहितार्थ हो सकते हैं: मौद्रिक नीति को गैर-प्रमुख घटकों में अल्पकालिक,

तालिका 6: सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन का परीक्षण

जनवरी, 2012 से नवंबर, 2019			
आश्रित चर: $\pi_t^{Headline} - \pi_{t-12}^{Headline}$			
	ढाल गुणांक	संख्याओं के लिए पी-मान	R ²
$\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}$	-0.96***	0.000	0.47
आश्रित चर: $\pi_t^{Core} - \pi_{t-12}^{Core}$			
$\pi_{t-12}^{Headline} - \pi_{t-12}^{Core}$	-0.045	0.6865	0.002

*** p<0.01, ** p<0.05.

चित्र 28: सीपीआई-सी हेडलाइन मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में प्रत्यावर्तन



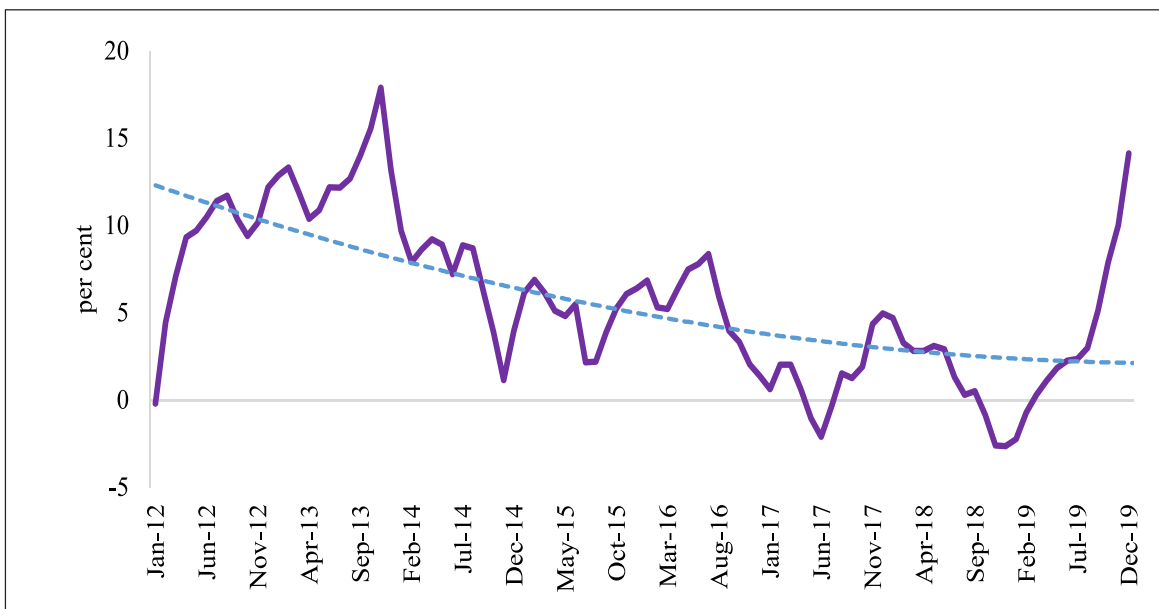
स्रोत: जनवरी, 2012 - नवंबर, 2019 की अवधि के लिए सीपीआई-सी आंकड़ों पर आधारित परिकलन

बीच-बीच में लगने वाले झटकों के मद्देनजर ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, भारत में उपभोक्ताओं की उपयोग मदों के अंतर्गत खाद्य एवं ईंधन को अधिक महत्त्व तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न केवल आपूर्ति पक्ष के कारक बल्कि मांग पक्ष की ओर से पड़ने वाले दबाव भी खाद्य और ईंधन संबंधी मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) के लिए महत्वपूर्ण

होते हैं, मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

5.35 भारत में मुद्रास्फीति की बदलती गतिकी में संभवतः दो मुख्य कारकों का योगदान है। प्रथम, हम पाते हैं कि विचारित अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रकृति देखी गई है (चित्र 29)। मुद्रास्फीति में यह

चित्र 29: उपभोक्ता खाद्य मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति)

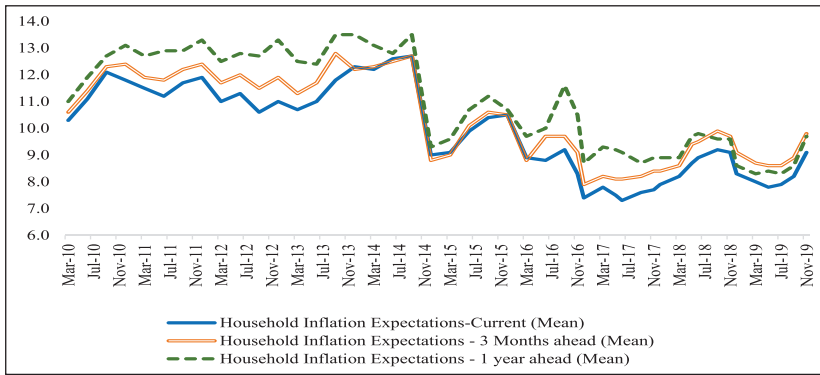


स्रोत: एन एस ओ

गिरावट खाद्य समूह की अधिकांश श्रेणियों में देखी गई है जिनमें उच्च भारांक वाली मर्दें, जैसे कि अनाज और इनके उत्पाद, फल, सब्जियां, दालें और इनके उत्पाद, भी शामिल हैं। दूसरे मुद्रास्फीति अपेक्षायें वर्ष 2015 से ही गिरावट दर्शाते हैं (चित्र 30) ऐसा अंशतः, मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को थामने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंगीकृत मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण उपागम की सफलता के कारण हो सकता है। वहीं दूसरी

ओर, घरेलू वस्तुओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं प्रायः खाद्य मुद्रास्फीति के आस-पास बनी रहती है। हो सकता है कि समग्र घरेलू मर्दों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में कमी इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के प्रभावस्वरूप आई हो। यह इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि उन घरेलू मर्दों का अनुपात, जिनके संबंध में एक वर्ष आगे के लिए खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा की गई, उसमें सितंबर, 2013 और

चित्र 30: घरेलू मर्दों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

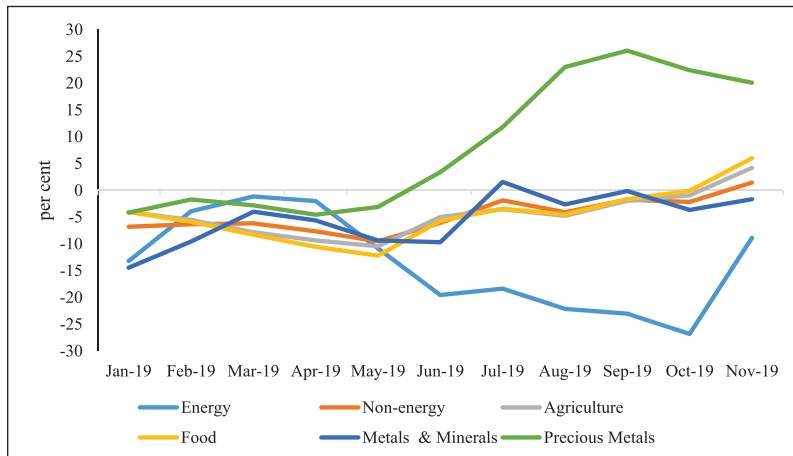
नवंबर, 2019 के बीच लगातार गिरावट हुई है।

वैश्विक वस्तु कीमतों में वैश्विक रुझान

5.36 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार, ऊर्जा पण्यवस्तु कीमतों ने वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। इनमें, वर्ष 2018-19

(अप्रैल-नवंबर) में 35.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर में (-) 16.8 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति दर्ज की गई)। खाद्य कीमतों के संदर्भ में, अवस्फीति की प्रवृत्ति जारी रही, जिसके अनुसार मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 0.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर)

चित्र 37: वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (जन. 2019 - नव. 2019)



स्रोत: विश्व बैंक

में (-) 4.3 प्रतिशत रही। धातु एवं खनिज सूचकांक में भी अवस्फीति की प्रवृत्ति देखी गई है, जो वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर लगातार धीमे आर्थिक परिदृश्य का संकेत देता है

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय

5.37 सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने हेतु समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें व्यापार और राजकोषीय नीति तन्त्रों का प्रयोग जैसे आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमाओं को लागू करना तथा जमाखोरों और कालाबाजारियों आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के संबंध में राज्यों को परामर्श साथ ही साथ सरकार उत्पादन वृद्धि हेतु समर्थन मूल्यों की घोषणा करके किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और ऐसी योजनाएं अमल में ला रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उचित उपायों के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इन योजनाओं में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी मिशन (एमआईडीएच) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम), राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम संबंधी मिशन (एनएमओओपी) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि-बागवानी समूह की वस्तुओं की कीमतों में कमी और अस्थिरता को संभालने हेतु 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' (पी एस एफ) का कार्यान्वयन भी कर रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान अगस्त, 2019 से प्याज की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, और स्थिति को सामान्य बनाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कई उपाय किए गए हैं:-

- वर्ष 2019-20 के दौरान, महाराष्ट्र (48183.5 मीट्रिक टन) तथा गुजरात (9,189.4 मीट्रिक टन) से खरीद के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत 57,372.90 मी.ट. प्याज का सुरक्षित भंडार तैयार किया गया है। जो कि विभिन्न राज्य सरकारों को वितरित किया गया और अन्य एजेंसियों को खुली निविदा के माध्यम से मंडियों में बेचा गया।

- कीमत एवं उपलब्धता की स्थिति में सुधार हेतु हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को हानि-लाभ रहित आधार पर प्याज की आपूर्ति की गई है। जुलाई से अक्टूबर 2019 के दौरान से दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी, एनसीसीएफ, एनएएफईडी और दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र के माध्यम से सीधे खुदरा मूल्य पर बफर स्टॉक की आपूर्ति की गई थी ताकि उचित मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एम ई आई एस) के अंतर्गत प्याज निर्यातकों के लाभ की व्यवस्था को दिनांक 11.06.2019 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिया गया है।

- दि. 13 सितम्बर 2019 को ब्याज पर 850 डॉलर/एम टी का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) आरोपित किया गया और तदनुसार उसके लगातार बढ़ते कीमतों को देखते हुए सरकार ने 29 सितम्बर 2019 को इसके निर्यात पर राक लगा दी।

- सरकार ने 29 सितंबर, 2019 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पूरे देश में व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा-खुदरा व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल निर्धारित कर दिया है। जो कि बाद में परिवर्तित करके स्टॉक सीमा खुदरा व्यापारियों के लिये 20 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिये 250 क्विंटल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से जमाखोरी, सट्टा व्यापार तथा मुनाफाखोरी, उत्पादक संघ (कार्टेलिंग) आदि जैसे अनुचित एवं अवैध व्यापार कार्यों को रोकने हेतु प्याज निर्यातकों के साथ राज्य तथा जिला स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है।

- सुगंधीकरण शर्तों में ढील देकर और भंडारण सीमाओं से आयातकर्ताओं के छूट देकर प्याज के निजी आयातों को सुकर बनाया गया।

- सरकार ने एमएमटीसी के द्वारा प्याज का अन्य देशों जैसे मिस्र और टर्की से आयात किया और नाफेड को राजस्थान, महाराष्ट्र से अतिरिक्त प्याज का क्रय करने और घाटे वाले राज्यों में वितरित करने का निर्देश दिया था।

निष्कर्ष:

5.38 कुल मिलाकर, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति कम रही, वहीं सी. पी. आई-सी मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित थी। कृषि

वस्तुओं में आपूर्ति पक्ष के झटके जैसे कि अनियमित बारिश के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई। सरकार वस्तुओं में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। दलहन के अलावा अधिकांश आवश्यक कृषि वस्तुओं के मूल्यों में मुद्रास्फीति में अस्थिरता भी समय के साथ कम हो गई है। हालाँकि, एक प्रमुख मुद्दा जो अभी भी बना हुआ है, वह है प्याज और टमाटर जैसी कुछ वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच अत्यधिक अंतर होना है। विभिन्न केंद्रों में प्याज और टमाटर जैसी कुछ वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच भिन्नता के कई कारण हैं जिसमें बड़ी संख्या में बिचौलिए और उच्च

परिवहन लागत प्रमुख हैं। राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, राज्यों में मुद्रास्फीति में भिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रत्येक राज्य के भीतर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच भी मुद्रास्फीति में एक विचलन पाया जाता है। समय के साथ ही मुद्रास्फीति की गतिशीलता में बदलाव आया है। मौजूदा अवधि में शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में जोरदार प्रत्यावर्तन होने के प्रमाण हैं। भविष्य में मुद्रास्फीति की संभावना और मुद्रास्फीति की गतिशीलता महत्वपूर्ण रूप से समग्र सूक्ष्म आर्थिक परिदृश्य के साथ-साथ कुछ कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लगाम लगाने पर निर्भर करती है।

अध्याय: एक नजर में

- 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 3.7% की तुलना में 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.1% थी।
- 2019-20 के दौरान, डब्ल्यू पी आई आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से घटकर नवंबर, और दिसंबर 2019 में 2.6% रही है।
- खाद्य सूचकांक जिसमें 2017-18 और 2018-19 के बीच वार्षिक आधार पर गिरावट आई, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2019) के दौरान तजी देखी गई।
- जुलाई 2018 के बाद से सीपीआई शहरी क्षेत्र मुद्रास्फीति, सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र मुद्रास्फीति, सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र मुद्रास्फीति से लगातार उपर रही है जो कि पिछले रुझानों के विपरित है जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति, शहरी मुद्रास्फीति से ऊंची रहती थी।
-
- 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, खाद्य और पेय पदार्थ सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे और इस अवधि के दौरान कुल मुद्रास्फीति के 54% के लिए उक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ जिम्मेदार है।
- देश के चार महानगरों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं में खुदरा इतने वर्षों के थोक मूल्यों से पृथक जा रहे हैं। वर्ष 2012 से ही मुद्रास्फीति की गति में बदलाव आया है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मूल मुद्रास्फीति में जोरदार प्रत्यावर्तन होने के प्रमाण हैं। तथ्य गैर मुख्य घटकों तक मुद्रा स्फीति का अंतरण न्यूनतम है। अतः मुद्रास्फीति के गैर-मुख्य घटकों में बदलाव के साथ आते झटकों के प्रति मौद्रिक नीति की अनुक्रिया ना करने की स्थिति बन सकती है।
- वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में पन्द्रह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू टी) में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे थी। वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में वास्तविक मुद्रास्फीति आठ राज्यों में घटी है।
- मुद्रास्फीति प्रत्याशा घटी है जो कि यह दर्शाता है कि लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति तन्त्र ने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

संदर्भ

आयोग, नीति, 2018, “स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इण्डिया”।

आनन्द आर. डिंग डी. तुलिन वी. 2014। फूड इनफ्लेशन इन इण्डिया: रोल ऑफ मोनेटरी पालिसी। आईएमएफ।

क्रिसिल 2017।” पलसैस एण्ड रिदम्स: अनैलाइजिंग वोलेटिलिटी, साइक्लिकलिटी एण्ड कॉबवैब फिनोमेन इन प्राइसैस” [Http://www.crisil.com](http://www.crisil.com).

ढोलकिया, कडियाला, 2018 “चेन्जिंग डयनैमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इण्डिया” इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली वाल्यूम स्पेस संख्या 9

आईएमएफ, 2019 वल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक

कुण्ड; सुजाता, 2018 रूरल वेज डायनैमिक्स इन इण्डिया; वाट रोल डज इनफ्लेशन प्ले: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वर्किंग पेपर

राज जे. मिश्रा एण्ड एस, 2011 “मेजर्स ऑफ कोर इन्फ्लेशन इन इण्डिया एन इम्पिरिकल इवेलुएशन।” रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वर्किंग पेपर सिरीज नं. 16/2011

शर्मा अनिल, प्रमोद कुमार, 2001 एन एनैगिलिसिस ऑफ दि प्राइस बिहेवियर ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज। प्लानिंग कमिशन

विश्व बैंक, 2019” इनफ्लेशन इन इमर्जि एण्ड डेवलपिंग इकॉनॉमीज, ड्राइवर और पालिसीज <http://www.worldbank.org/inflash>